quately. We have only bogged ourselves into this controversy—useless controversy, futile controversy, of Hindi and English.

I am not speaking Hindi; I cannot speak Hindi; I cannot speak chaste Hindi at least. If I wanted to express myself in Hindi, I can do so, but not in a chaste way. But even English is not my mother-tongue; not yours either, and there are very few people in this House in whose case English is the mother-tongue. But in spite of that, we have been brought up in the tradition of English literature and all that.

Would you like me to stop here and give me time tomorrow or could I finish now?

MR. DEPUTY-SPEAKER : We are adjourning now; she may continue her speech when we resume this debate next time. That will be all right.

DR. MAITREYEE BASU : Thank you, Sir.

12.59 HRS.

The Lok Sabha then adjourned for lunch till fourteen of the Clock.

The Lok Sabha re-assembled after Lunch at Fourteen of the Clock.

[MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*]

MOTION OF NO-CONFIDENCE IN THE COUNCIL OF MINISTERS—*contd.*

श्री मधु लिमये (मुंगेर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि—

"यह सभा वर्तमान मंत्री परिषद् में अपने विश्वास के अभाव को व्यक्त करती है।"

उपाध्यक्ष महोदय, वैसे तो यह प्रस्ताव इस सत्र के पहले दिवस ही आने वाला था, लेकिन हम लोगों ने सोचा कि आपको पहले मौका दिया जिस गलत रास्ते पर आप चल पड़े हैं उस से वापस हटने का और इसी लिये गवर्नर की नियुक्ति, गवर्नर के अधिकार—इन के बारे में यहाँ पर बहस उठाई गई। हमें आशा थी कि इस बहस का सरकार पर कुछ अच्छा असर पड़ेगा, लेकिन खेद के साथ कहना पड़ता है कि इस बहस का सरकार के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा और जो गलत फैसला, जो खतरनाक फैसला हम चाहते थे कि यह सरकार न करे, वही उन्होंने किया। पहले तो पश्चिमी बंगाल के बारे में किया था, लेकिन बाद में सोचा कि लोग कहेंगे कि बंगाल के खिलाफ जान-बूझ कर यह कार्यवाही की गई है, बंगाल के ऊपर बलातकार किया गया, लोकतंत्र का वहां गला घोटा गया, तो इन्होंने सोचा कि हरियाणा पर भी बलात्कार करेंगे तो दो बलात्कार होने के कारण जनता हम को माफ करेगी और इसी लिये हरियाणा के बारे में भी सरकार ने गलत फैसला किया। लेकिन यह बात बिल्कुल साफ़ थी कि दोनों के बारे में फैसला एक ही समय हुआ था। हो सकता है कि आज प्रधान मंत्री और गृह मंत्री यहां पर कहें कि पश्चिमी बंगाल में जो हुआ उस के बारे में हमें कुछ नहीं कहना है, क्योंकि राज्यपाल ने अपने विवेकपूर्ण अधिकार का इस्तेमाल कर के यह काम किया है। लेकिन इस तरह की बातों का जनता के ऊपर कोई असर नहीं पड़ने वाला है।

सदन में दो-तीन रोज़ से बहस चल रही है। कल हरियाणा के गवर्नर का प्रवचन हम ने सुना—दल परिवर्तन की प्रवृत्ति के बारे में और हम को बताया गया कि दल परिवर्तन के कारण वहां पर अस्थिरता उत्पन्न हो गई है और इस अस्थिरता को खत्म करने के लिये और जो दल छोड़ने वाले लोग हैं, दल बदलने वाले लोग हैं, उन को दण्डित करने के लिये वहां हम, विधान सभा को बरखास्त कर रहे हैं, सरकार को हटा रहे हैं और दोबारा चुनाव कराने जा रहे हैं तो हरियाणा में दल छोड़ने वालों को दण्डित करने का प्रयास किया गया, लेकिन आज आप लोग देख रहे हैं कि पश्चिमी बंगाल में जो दल छोड़ने वाले लोग हैं, दल परिवर्तन करने वाले लोग हैं, उन को भेंट में उपहार दिया जा रहा है। पी० सी० घोष साहब मुख्य मंत्री बनाये गये हैं, उस का एकमात्र मतलब है कि कांग्रेस सरकार विरोधी दलों से जब लोग टूटते हैं तो उन का स्वागत करती है।

कल चव्हाण साहब ने गया-राम और आया-राम की बात कही थी। मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी को गुस्सा है उन लोगों से जो उनका दल छोड़ जाते हैं, गया-रामों से उन को गुस्सा है। विरोधी दल अगर टूटता है और उन दलों से कांग्रेस के अन्दर लोग चले आते हैं तो इन आया-रामों से उन को नफरत नहीं है, उन के लिये तो सुस्वागतम है, और इसी लिये न केवल पश्चिमी बंगाल में बल्कि इसी तरह की कार्यवाही बिहार में करने के लिये उन्होंने अपनी इच्छा के अनुसार एक गवर्नर को बिहार पर लादने का फ़ैसला किया है। आज इस सदन को मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि जो पश्चिमी बंगाल में हुआ है, वही कल बिहार में होनेवाला है और उस के बाद उत्तर प्रदेश का नम्बर होगा। तो जैसा कि हम लोगों ने मार्च-अप्रैल महीने में कहा था, हिन्दुस्तान में चौथे चुनाव के बाद युग परिवर्तन शुरू हुआ है, कांग्रेस का जो एकाधिकार था—केन्द्र और राज्य में, वह एकाधिकार खत्म होकर गैर-कांग्रेसी सरकारों के निर्माण का एक युग, एक प्रक्रिय शुरू हुई है। उस वक्त बात बिलकुल साफ थी कि या तो इस प्रक्रिया को हम लोग आगे ले जा कर इस सरकार को अपदस्थ करें, वर्ना अगर इन लोगों के हाथ में केन्द्रीय सरकार रही और ये सारे अधिकार रहे तो इन अधिकारों का दुरुपयोग कर के जनता ने जो मत व्यक्त किया था चौथे चुनाव में, उस मत के खिलाफ़ जाकर ये गैर-कांग्रेसी सरकारों को नाजायज़ ढंग से खत्म करने की चेष्टा करेंगे—आज वही हो रहा है।

आज संविधान की हत्या हो रही है। संविधान के अन्दर राज्यों को जो स्वायत्तता थी, राज्यों के जो अधिकार थे, उन सीमित अधिकारों को भी आज यह केन्द्र सरकार खत्म कर रही है और हम आज यह बात कहने के लिये बाध्य हो रहे हैं कि राज्य सरकारों की हैसियत नगरपालिकाओं से ज्यादा नहीं है। नगरपालिकाओं को भी ज्यादा गम्भीरता से विचार करने पर, राज्य सरकारें कभी-कभी तोड़ दिया करती हैं, लेकिन इन लोगों ने जान-बूझ कर संविधान की सारी धाराओं की अवहेलना कर के इन राज्य सरकारों को खत्म करने का काम किया है। क्या नतीजा होने वाला है?

उपाध्यक्ष महोदय, 9-10 साल पहले पाकिस्तान में भी यही स्थिति पैदा हुई थी और संविधान के साथ जिस तरह वहाँ पर खिलवाड़ हुआ, उस का यह नतीजा हुआ कि सेना ने इस में हस्तक्षेप किया और वहां पाकिस्तान में सैनिक शासन कायम हुआ। चार-पांच साल पहले अगर हिन्दुस्तान में सैनिक शासन की कोई चर्चा करता तो सभी लोग कहते —हो सकता है कि यह पाकिस्तान में हुआ, बर्मा में हुआ, दूसरे देशों में हुआ, लेकिन हिन्दुस्तान में यह कभी नहीं होगा, क्योंकि हिन्दुस्तान में हमारा संविधान है, चार दफ़ा चुनाव हुए हैं, यहां एक लोकतन्त्रीय प्रणाली है, परम्परा है, इस लिये सैनिक शासन इस देश में असम्भव है—यह हम को कहा जाता लेकिन धीरे-धीरे हम लोग देख रहे हैं कि हिन्दुस्तान में नागरिकों के खिलाफ़, उन की शहरी आजादी के खिलाफ़ धीरे-धीरे सेना का इस्तेमाल किया जा रहा है।

मैंने कुछ दिन पहले सुना, जानकार सूत्रों से पता चला—एक बड़े उद्योगपति ने एक बड़े जैनरल को खाने पर बुलाया था और उस वक्त इस बात की चर्चा हुई थी और उस जैनरल ने उस उद्योगपति से कहा—आप हम को हस्ताक्षेप करने के लिये दावत दे रहे हैं, तो फिर ऐसा समय आयेगा जब हम लोगों को कहना पड़ेगा, अगर आप लोग सम्भाल नहीं सकते हैं और सेना का इस्तेमाल गैरफौजी कामों के लिये करना चाहते हैं, अपने ही नागरिकों के खिलाफ अगर सेना का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो फिर सारा कारोबार आप सेना के सुपुर्द कर दीजिये। तो इस तरह के विचार आज सेना में और सेना

[श्री मधु लिमये]

के जो बड़े अधिकारी हैं, उन लोगों में इस तरह के विचार आने लगे हैं, तो मैं सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं कि अगर इसी रास्ते पर यह सरकार चलती रही तो देश में न केवल गैर-कांग्रेसी सरकारें खत्म होंगी, बल्कि एक समय ऐसा आयेगा जब हिन्दुस्तान में लोकतन्त्रिक शासन भी खत्म हो जायेगा और फिर उस में इन्दिरा गांधी जी और चव्हाण साहब भी नहीं बचने वाले हैं।

आज उपाध्यक्ष महोदय, हमारे सामने जो सवाल है वह केवल कानूनी नहीं है। संविधान की धाराओं में बारीकी से जाकर उस की चर्चा करने का सवाल नहीं है। यह राजनीति का सवाल है और कांग्रेस के द्वारा जो क़दम इस के पहले उठाये गये थे और आज उठाये जा रहे हैं उस के पीछे एक ही भावना है कि कांग्रेस पार्टी एकाधिकार शाही की इतनी आदी हो गई है कि वह किसी भी हालत में सत्ता को नहीं छोड़ना चाहती।

हम लोगों में से कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने कि स्वतंत्रता के बाद 18–20 साल तक विरोधी दलों में रह कर अपने सिद्धान्तों के अनुसार काम किया है। लेकिन क्या वजह है कि 20 साल के बाद जब कांग्रेस को 8–9 राज्यों में हुकूमत को छोड़ना पड़ा, जनता ने हराया तो ये लोग एक, दो महीने के अन्दर गैर-कांग्रासी सरकारों को खत्म करने के लिए कार्यवाहियां करने लगे, षड़यन्त्र रचने लगे और उस काम में केन्द्रीय सरकार ने हमेशा उन की सहायता की ? जब कभी केन्द्र और राज्य के रिश्ते के बारे में यहां बहस उठाई जाती है तो हमेशा हम को जवाब मिलता है कि गैर-कांग्रेसी सरकारों के साथ कोई विषम व्यवहार हम लोग नहीं कर रहे हैं। हम उन के साथ समानता का व्यवहार कर रहे हैं। लेकिन धीरे-धीरे बात बिलकुल साफ हो रही है कि अपने केन्द्रीय अधिकारों का नाजायज ढंग से इस्तेमाल करके इन सरकारों के ऊपर रोक लगाई जा रही है।

मैं यह मानता हूं कि गैर-कांग्रेसी सरकारों का निर्माण होने के पश्चात् जिस ढंग से उन सरकारों को काम करना चाहिए वह काम नहीं हुआ है और हम लोग चाहते थे कि गैर-कांग्रेसी सरकारें कार्यक्रम अभिमुख बनें, नीतियों का पालन करें और कार्यक्रमों को जल्दी अमल में लायें। वह बात नहीं हो पाई है मैं मानता हूं लेकिन उस का यह मतलब नहीं है कि इस से कांग्रेस को कोई अधिकार मिल जाता है इन सरकारों को ख़त्म करने का।

आज का यह प्रस्ताव केवल कांग्रेस पार्टी ने, केन्द्रीय सरकार ने हरियाणा में और बंगाल में जो किया उस को लेकर ही नहीं है। जो इन की बराबर नीतियां रहीं मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं कि जब दल परिवर्तन की निन्दा चव्हाण साहब करते हैं तो वह भूल जाते हैं कि दल परिवर्तन की ख़तरनाक प्रवृत्ति इन्हीं लोगों ने हमारे देश में कायम की। मैं उन से पूछना चाहता हूं कि 1952 में राजस्थान में यह हार चुके थे अगर विरोधी दलों से कुछ लोगों को लालच दिखा कर अगर यह लोग अपने दल में नहीं ले आते तो सन् 1952 में भी राजस्थान में इन की सरकार नहीं बन सकती थी। सन् 1962 में आप जानते हैं मध्य प्रदेश में यह हार चुके थे। उस वक्त भी विरोधी दलों में फूट डाल कर और उन लोगों को अपने दल में शामिल करके इन लोगों ने अपना बहुमत कायम किया और मध्यप्रदेश सरकार पर यह हावी हो गये चौथे आम चुनाव के बाद सब से पहले दल परिवर्तन की प्रवृत्ति को कांग्रेस पार्टी ने चालू किया उसे प्रोत्साहन दिया। अगर यह प्रवृत्ति नहीं होती तो राजस्थान में इन की सरकार नहीं बनती लेकिन राजस्थान में सुखाड़िया साहब सरकार की बागडोर को छोड़ना नहीं चाहते क्योंकि उन के खिलाफ तरह तरह के इलज़ामात थे। यह सोना कांड का भी मामला था और वह अच्छी तरह जानते थे कि अगर वह सत्ता में नहीं रहगे तो जो नई सरकार आयेगी जिस तरह बिहार में

मंत्रियों के खिलाफ़ जो अभियोग लगाये गये हैं उन की जांच करने के लिये वहां कमिशन बैठाया गया इसी तरीक़े से राजस्थान में भी होता और यही वजह है कि राजस्थान में दल परिवर्तन के जरिए उन्होंने अपनी सरकार को जमाया। उत्तर प्रदेश में भी आप जानते हैं कि 15 दिन जो चन्द्रभानु गुप्त की सरकार बनी। विरोधी दलों से लोगों को तोड़ कर ही इस सरकार का संगठन किया गया। इसलिए जहां तक दल परिवर्तन का सवाल है यह कांग्रेस पार्टी ही दोसी है उसी के द्वारा यहप्रवृत्ति चलाई गई है और उसका साफ़ मतलब है कि कांग्रेस पार्टी आया-रामों का स्वागत करेगी लेकिन जोगया राम हैं उन का स्वागत करने के लिए वह तैयार नहीं हैं। उस को वह बहुत ख़तरनाक समझते हैं।

SHRI SHASHI RANJAN (Pupri): I would like to rise on a point of order. He has just now mentioned about Bihar. An inquiry commission has been instituted there.

AN HON. MEMBER: Against Shri K. B. Sahay.

SHRI SHASHI RAJAN: No finding has come yet. Prior to this they had instituted a one-man inquiry committee constituted of Shri Bakshi. He gave a clear signal... (*Interruptions*).

MR. DEPUTY SPEAKER: Please resume your seat. What he has referred to is only inquiry. Beyond that, he has not said anything.

श्री मधु लिमये:

उपाध्यक्ष महोदय, जिस तरह नैतिकता, लोकतंत्र और संविधान, का ख़ात्मा इस सरकार ने किया है उसी तरीक़े से देश की जो अर्थ-व्यवस्था है खेती और कारखाने, और हमारे आयात, निर्यात और व्यापार उस को इस सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में चौपट किया है। हमारे लायक़ दोस्त श्री अशोक मेहता जब कांग्रेस में गये तो उन को उपाध्यक्ष बनाया गया योजना आयोग का...

एक माननीय सदस्य: काबलियत पर बने।

श्री मधु लिमये: मैंने तो कहा मेरे लायक़ दोस्त, आप ने सुना नहीं। बहुत लायक़ हैं। वह जब गये तो उपाध्यक्ष महोदय, कुछ लोगों का ख़याल था कि वह बड़े विद्वान आदमी हैं, अर्थ शास्त्री हैं। योजना आयोग में जाने के पश्चात् देश की जो आर्थिक तरक्की का ढांचा और नक़शा वह बनायेंगे लेकिन उन के जाते ही उन्होंने पंचवर्षीय योजनाओं को ही समाप्त कर डाला। चौथी पंचसाला योजना अब तक इस सदन् के सामने नहीं आई है और अब जो नये उपाध्यक्ष हैं उन्होने यह कहा है कि शायद यह पांच साल की जो अवधि है उस में यह चौथी योजना नहीं आ पायेगी। हर साल हम कोई एक साल की योजना बनायेंगे और इस देश के सामने लायेंगे।

कहा जाता है कि चीनी आक्रमण के कारण या पाकिस्तान के साथ जो लड़ाई हुई उस के कारण सुरक्षा का बोझ बढ़ा, खर्चा बढ़ा इसलिए हमारी आर्थिक प्रगति में, तरक्की में बाधा उत्पन्न हुई।

लेकिन राष्ट्रीय आमदनी के अगर आप आंकड़े देखेंगे तो आप को पता चलेगा कि चीनी आक्रमण के पहले ही हमारी जो रफ़्तार है वह धीमी पड़ चुकी थी, आर्थिक प्रगति का रास्ता कुंठित हो गया था और मैं तो यहां तक जाकर कहूंगा कि चीनी आक्रमण भी इसीलिये शायद हुआ क्योंकि इन्होंने देखा कि हिन्दुस्तान सभी दृष्टियों से कमजोर हो रहा है। सुरक्षा की दृष्टि से, विदेश नीति की दृष्टि से, संकल्प शक्ति की दृष्टि से भी, आर्थिक और औद्योगिक दृष्टि से भी क्योंकि चीनी आक्रमण के पहले दो वर्षों में हमारी आर्थिक प्रगति एकदम रुक गई थी और चीनी आक्रमण के पश्चात् यह जो सिलसिला पहले से शुरू हुआ था वह सिलसिला और जोरों से चालू रहा।

तीसरी पंचसाला योजना में उन लोगों ने राष्ट्रीय आमदनी बढ़ाने के बारे में जो लक्ष्य अपने सामने रक्खा था उस को ये लोग आधा भी पूरा नहीं कर पाये और चौथी पंचसाला

[श्री मधु लिमये]

योजना के पहले दो वर्षों की आर्थिक स्थिति अगर हम देखेंगे तो आर्थिक स्थिति सुधारने के बजाय और खराब होती जा रही है। सरकार की जितनी सारी नीतियां हैं उन नीतियों का यह नतीजा निकला है कि हमारी पैदावार बढ़ने के बजाय अवरुद्ध हो गई है। सरकार की किसी भी नीति को आप देख लीजिये। इसी सत्र में और उस के बाद सरकार ने सीमेंट के बारे में चीनी के बारे में रूई के बारे में नई-नई नीतियां अपनाई। आप जानते हैं कि दीवाली के अवसर पर पूजा के अवसर पर, चीनी के दाम इस देश में 7 रुपये, 8 रुपये और 9 रुपये किलो तक हुए थे। और उस का कारण यह है कि उन की जो चीनी के बारे में नीति है वह जो उपभोक्ता है, नागरिक है, उस के हित में नहीं है। मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं कि उन की नई नीति के कारण चीनी पैदा करने वाले जो कारखाने वाले हैं, उन को एक टन के पीछे 300 या 400 रुपया अतिरिक्त मुनाफा होने वाला है। इस का मतलब है कि अगर चीनी की पैदावार इस साल 25 लाख टन हुई तो 10 लाख टन मुक्त व्यापार के जरिये बेची जा सकती है। एक टन पर अगर 400 रुपया मिलता है तो 10 लाख टन पर 40 करोड़ रुपया अतिरिक्त मुनाफा कारखानेदारों को मिल जायेगा। उस के बाद वितरण करने वाले लोग भी जनता को लूटेंगे वह एक दूसरी बात है। इस तरह से सरकार की चीनी सम्बन्धी जो नीति है उस का साफ नतीजा यह हुआ कि 40 करोड़ रुपया मिल मालिकों को अतिरिक्त मुनाफे के तौर पर मिला। जब इस तरह की सुविधा यह सरकार मिल मालिकों को देती है और उपभोक्ताओं को लूटने का अवसर उन लोगों को मिलता है तो जरूर उस के पीछे कोई न कोई षड़यन्त्र है। मुझ को कलकत्ते में खबर मिली है कि इस तरह की नीति अपनाने के लिये जब सरकार का मन परिवर्तित किया गया तब उन लोगों को 25 लाख रुपये घूंस के तौर पर दिये गये हैं। मैंने जानकार सूत्रों से इस का पता लगाया है। जब इस तरह की बातें हमारे देश में होंगी...

एक माननीय सदस्य : सिर्फ 25 लाख रुपया ?

श्री मधु लिमये : क्या 25 लाख रुपया कम है ? सारी लाज और शर्म इन लोगों ने छोड़ दी है। यह लोग कहते हैं कि 25 लाख रुपया भी जो रिश्वत के तौर पर दिया गया है, वह कम है।

सीमेंट के बारे में भी आप जानते हैं कि जब लोगों को सहूलियत दी गई, जब उस के दाम बढ़ाए गये तब सरकार सीमेंट में से जो हिस्सा लेने वाली थी वह उस ने पूरा नहीं लिया। जो भी सीमेंट बच गया उस को खुली मंडी में बेचने का उन को मौका मिला। उस से जो पैसा उन लोगों को मिला उस का इस्तेमाल उन्होंने राजनीति पर अपना असर डालने के लिये और इस संसद् को गुलाम बनाने के लिये किया। खुल्लम खुल्ला इस तरह के बयान निकले हैं कि सीमेंट उद्योग ज्यादा मुनाफा कमाये इस के लिये जो प्रयत्नशील रहेंगे उन को मदद करने के लिये इस पैसे का इस्तेमाल करना कोई भ्रष्टाचार नहीं है, कोई अनुचित काम नहीं है। इस लिये खुल्लम खुल्ला उन लोगों के द्वारा यह काम किये गये।

निर्यात व्यापार के बारे में आप से निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार की जितनी सारी नीतियां रही हैं, उन का नतीजा यह हुआ है कि जो भ्रष्टाचारी पूंजीपति हैं, कारखाने वाले हैं, उन को हमेशा बढ़ावा मिला है। कई मामलों को मैंने इस सदन में उठाया है। आप जानते हैं कि व्यापार मंत्रालय के तहत जो टेक्स्टाइल कमिश्नर का कार्यालय है, ज्वायेंट चीफ कंट्रोलर आफ इम्पोर्टस एन्ड एक्सपोर्टस का कार्यालय है, उस के बारे में कई किस्म की शिकायतें मैंने की, और इस इस लिये नहीं कि वह कोई छोटी बात थी, बल्कि इस लिये कि जो हमारी नौकरशाही है, मंत्री शाही है और बेईमान पूंजीपति हैं, इन तीनों ने मिल कर

देश की अर्थ-व्यवस्था को चौपट किया है। इस लिये जहां-जहां इस तरह के नाजायज काम हम को देखने को मिलते हैं, उन के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश हम करते हैं। लेकिन यह सरकार कभी इसके बारे में जांच करने के लिये तैयार नहीं है। दोराईस्वामी जैसे भ्रष्ट अधिकारी के बारे में सबूत के साथ एक नहीं सात आरोप पेश किये गये। सबूत देने के बाद भी क्या वजह है कि इस सरकार ने अभी तक इस अधिकारी को मोअत्तल नहीं किया है, निकाला नहीं है? इस का कारण यह है कि यह सारे अधिकारी जो काम करते हैं, मैं मानने के लिये तैयार नहीं हूं कि मंत्रियों को उन का पता नहीं रहता है, मंत्रियों को उन का पता रहता है, लेकिन उन का भी उस में हिस्सा रहता है, और बार बार पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने इस को साबित भी किया है। उस ने बार बार कहा है कि पूंजीपति, मंत्रीशाही और नौकरशाही तीनों के अपवित्र गठबन्धन से आज हमारी अर्थ व्यवस्था खत्म होती जा रही है।

इस लिये आज भ्रष्टाचार को बनाये रखने वाली, आर्थिक प्रगति में बाधा डालने वाली, चीनी का मामला हो, सीमेंट का मामला हो, उपभोक्ताओं को लूटने की नीति अपनाने वाली जो सरकार है उस को हटाने के लिये यह प्रस्ताव हम लोग लाये हैं।

आप को याद होगा कि तीसरे चुनाव तक जब कभी चुनाव अभियान होता था तो हमेशा यह प्रचार किया जाता था कि कांग्रेस सरकार के रहते हुए दुनिया में हिन्दुस्तान की इज्जत बहुत ज्यादा बढ़ी है। 1962 तक यह भी प्रचार किया जाता था, और अभी भी यह लोग कहते हैं कि दुनिया भर के सभी देशों से मित्रता और सद्भाव के सम्बन्ध हमारे हैं। अमरीका हो, रूस से हो, इंग्लैंड हो, फ्रांस से हो, सभी से हमारे अच्छे रिश्ते हैं और चीन दिन प्रति दिन अलग पड़ता जा रहा है। लेकिन हम लोगों ने देखा चाहे जितनी भी सहानुभूति हिन्दुस्तान से दुनिया को रही हो, जब कसौटी का क्षण आया, जब लड़ाई का समय आया, तो जिस के बारे में कहा जाता था कि वह दुनिया से अलग पड़ गया है उसी चीन ने हम को हराया और आज दुनिया में हिन्दुस्तान की प्रतिष्ठा गिरी।

अभी-अभी मैं मास्को गया था। वहां एक किस्सा हुआ जो कि बड़ा ही दर्दनाक है, और शर्म के मारे हम को अपना सिर झुकाना पड़ता है। मुझे बतलाया गया कि वहां जो यंग पायोनियर्स होते हैं उन की एक सभा में रूसी सेना के एक अधिकारी वर्तमान संघर्षों के बारे में बोलते हुए अल्जीरिया का जिक्र किया, वियतनाम का जिक्र किया, अरब इजराइल का जिक्र किया और हिन्दुस्तान और पाकिस्तान का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पन्द्रह-सोलह दिन तक यह लोग आपस में लड़े। जब उन का बारूद, उन का ऐम्यूनिशन खत्म हुआ तो उस के बाद उन्होंने युद्धबन्दी को कबूल किया। इस पर आठ-नौ साल के लड़के हंस पड़े क्योंकि उन लोगों ने पहले महायुद्ध में, गृह-युद्ध में, क्रान्ति के समय और द्वितीय महायुद्ध में इतना बड़ा बलिदान कर के अपनी मातृभूमि की रक्षा की थी। लेकिन जब उन्होंने देखा कि 50 करोड़ का यह हिन्दुस्तान लड़ नहीं पाता है, आगे बढ़ नहीं पाता है और बारूद और हथियारों की कमी के कारण अन्त में यह दोनों देश युद्धबन्दी कबूल करते हैं, तब आप अन्दाज लगा सकते हैं कि उन बच्चों के मनों में भारत के बारे में क्या भावना पैदा हुई होगी।

किसी भी सरकार के लिये यह जरूरी है कि लोगों को खाना दिलाने के लिये बढ़िया इन्तजाम करे और मातृभूमि की रक्षा करे। जनता के खाने पीने का सवाल हल नहीं हुआ, लगातार जगह-जगह अकाल और कमी का सामना करना पड़ा, लेकिन खाना और पेट के मामले को मैं एक क्षण छोड़ता हूं, मगर किसी सार्वभौम राज्य के लिये यह आवश्यक है कि वह अपनी मातृभूमि की रक्षा

[श्री मधु लिमये]

करे। हमेशा कहा जाता है कि हमारे जो वामपन्थी कम्यूनिस्ट हैं वह देशद्रोही हैं, देश के प्रति उन की निष्ठा नहीं है। लेकिन मैं आज कहना चाहता हूं कि अगर वह लोग दिमाग से देशभक्त नहीं हैं तो कांग्रेसी आचरण में देशद्रोही हैं। कांग्रेसी लोग अपने काम में देशद्रोही हैं जब कि वह लोग केवल विचारों में हैं। हिन्दुस्तान की जो भूमि आज विदेशियों को दी गई है वह राममूर्ति जी के द्वारा या गोपालन साहब के द्वारा नहीं दी गई है। कम्युनिज्म के बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि जब तक वे अधिकार में नहीं आते हैं, वे अराष्ट्रीय होते हैं लेकिन जब वे अधिकार में आते हैं तो वे अतिराष्ट्रीवादी बन जाते हैं।

रूमानिया का उदाहरण आपके सामने है, युगोस्लिविया तथा अल्बानिया का है, चीन का है। लेकिन यह जो कांग्रेस पार्टी है ऐसी विचित्र पार्टी है कि जब विरोध में थी तब राष्ट्रीयता की भावना पर चल रही थी लेकिन अधिकार में आने के पश्चात् यह राष्ट्रद्रोही और देशद्रोही बन रही है और हमारी भूमि का एक-एक टुकड़ा विदेशियों को देती चली आ रही है (**इंटरप्शंस**) आपको क्यों बुरा लग रहा है, सही बात तो है। स्वतंत्रता के बाद जो हमारी ज़मीन थी आज वह उतनी नहीं रह पाई है। दुनिया में शायद ही कोई ऐसी सरकार हो कि जो अपनी सीमाओं की रक्षा न करने के पश्चात भी अधिकार में रही हो। लेकिन यहां लगातार यह सिलसिला चलता आ रहा है।

कुछ दिन पहले यहां पर बयान दिया गया और वह बयान श्री मोरारजी देसाई के द्वारा दो चीन वाली नीति के बारे में वक्तव्य दिया गया था उसके बारे में दिया गया था। मोरारजी भाई का वक्तव्य सुनने के पश्चात मुझे ऐसे लगने लगा था कि इनको कुछ अकल आ रही है लेकिन इन्दिरा गांधी जी का बयान सुनने के बाद मुझे ऐसा लगा कि यह मेरी गलतफहमी थी और इनको कभी अकल नहीं सूझी है।

आज विदेश नीति हमारी क्या है? किसी देश को या किसी राज्य को मान्यता देने के बारे में हमारी कोई नीति नहीं है, कोई सिद्धान्त नहीं है। आज कीसिंगर साहब का बयान मैंने देखा है। उन्होंने कहा है कि पूर्व जर्मनी को मान्यता देने वाले देश के बारे में हम ऐसा मानेंगे कि वे हमारे मित्र नहीं हैं, उनका व्यवहार दुश्मन जैसा है। क्या मतलब है इसका? इसको वे लोग हालष्टाइन डाक्ट्रिन कहते हैं। लेकिन जो डट कर आगे बढ़ता है उसके सामने इनका हालष्टाइन डाक्ट्रिन गायब हो जाता है। रूस के बारे में यह पहले से ही गायब था। लेकिन आप लोग जानते हैं कि इन दिनों में रूमानिया के साथ उन्होंने कूटनीतिक रिश्ते कायम किये हैं। क्या रूमानिया के राजनयिक रिश्ते, कूटनीतिक रिश्ते पूर्व जर्मनी के साथ नहीं हैं? फिर भी रूमानिया के साथ पश्चिमी जर्मनी को कोई एतराज नहीं है कूटनीतिक सम्बन्ध कायम करने को। लेकिन अगर हिन्दुस्तान यह सिद्धान्त रखता है कि जो राज्य अस्तित्व में है, जिसकी अपनी सरकार है, जिसकी अपनी सीमाएं हैं चाहे वह राज्य अच्छा हो सैद्धान्तिक दृष्टि से, वैचारिक दृष्टि से या खराब हो, पूंजीवादी हो या समाजवादी हो, कम्युनिस्ट हो या लोकतांत्रिक हो, तानाशाही राज्य हो या संसदीय प्रणाली वहां पर हो, उसका रंग क्या है इससे हमें मतलब नहीं है, अगर वह राज्य अस्तित्व में है, तो उसके साथ कूटनीतिक रिश्ते कायम करने की हमारी नीति है। इस तरह की नीति का एलान अगर इस सरकार के द्वारा होता तो आज जो हमारी फजीहत हो रही है वह नहीं होती। हम लोग इज़राईल को मान्यता तो देते हैं लेकिन कहते हैं कि इज़राईल के साथ कूटनीतिक रिश्ते हमारे नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? रूस रखता है, अमरीका रखता है, आपको क्या एतराज है? सोचते हैं अरब नाराज हो जायेंगे, पाकिस्तान को यह अच्छा नहीं लगेगा। इनका कोई अपना सिद्धान्त नहीं है। उसी तरह अध्यक्ष महोदय, पूर्व जर्मनी से ये नाता रिश्ता क्यों नहीं रखते हैं? इसलिए

नहीं रखते हैं कि पश्चिमी जर्मनी नाराज हो जाएगा। अमरीका नाराज हो जाएगा। जो राज्य अस्तित्व में है उसके साथ व्यापार तो बढ़ाना चाहते हैं लेकिन उसके साथ कूटनीतिक रिश्ते प्रस्थापित नहीं करना चाहते।

चीन के बारे में इनको क्या पड़ी थी यह कहने की कि फार्मुसा किस का है? असली बात तो यह है कि चीन की भूमि पर एक पेकिंग की सरकार है और फार्मुसा की भूमि पर च्यांग काई शेक की सरकार है। दोनों खराब हैं अपनी दृष्टि से। लेकिन उससे क्या मतलब। पेकिंग वाली सरकार खराब होते हुए भी, आक्रमणकारी होते हुए भी वहां पर है। उसके बारे में आप कहते हैं और हमेशा इस सरकार ने कहा है कि वास्तविकता को कैसे भुलाया जा सकता है। अमरीका के साथ इन्होंने विवाद किया कि वास्तविकता को आप नहीं भुला सकते हैं, इसलिए पेकिंग चीन को मान्यता देनी चाहिये। मैं इनसे कहूंगा कि फार्मुसा चीन भी वास्तविकता है, यह अच्छी वास्तविकता हो या नहीं है लेकिन इस वास्तविकता से मुंह फेर कर, आंखें मूंद कर हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं। सही नीति यही होती कि फार्मुसा सरकार को भी मान्यता पेकिंग सरकार को भी मान्यता, बान सरकार को मान्यता, उसी तरह से पूर्व जर्मनी को भी मान्यता, अरब राज्यों को मान्यता, उसी तरह इजराईल को भी मान्यता। वही बात मैं उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बारे में कहूंगा। दुनिया में जितने खंडित देश हैं उन के अलग-अलग राज्य बने हैं। इनके बारे में इस सरकार की कोई नीति नहीं है। मैं आज कहना चाहता हूं कि हमारी विदेश नीति हिन्दुस्तान में तय नहीं होती, कभी वह मास्को में होती है, कभी वह वाशिंगटन में होती है, कभी वह काहिरा में होती है और कभी किसी और जगह होती है।

जहां तक वियतनाम का सम्बन्ध है, मैं समझ सकता था अगर ये लोग चुप बैठते। तब इनको बिल्कुल चुप बैठना चाहिये था। लेकिन इन लोगों की नीति क्या है? इन्दिरा गांधी जी कालीकट में बोलीं तो कहा कि वियतनाम के बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है। फिर वाशिंगटन गईं, वहां जानसन साहब से मिलीं और वहां कहा कि मैं समझ सकती हूं अच्छी तरह कि अमरीकी लोग वियतनाम पर क्यों बमबारी कर रहे हैं। फिर मास्को गईं तो वहां जा कर इन्होंने आलोचना की कि अमरीकी लोग बहुत खराब काम कर रहे हैं। इस तरह आप देखेंगे कि इन लोगों की नीति बिल्कुल गंगा गए तो गंगादास और जमना गए तो जमना दास वाली हो गई है। कोई इनकी अपनी बुनियाद नहीं है, कोई इनका सिद्धान्त नहीं है। यही वजह है कि आज दुनिया में इनकी बिल्कुल हंसी हो रही है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : (बलरामपुर) : लेकिन ये हैं त्रिवेणी दास :

श्री मधु लिमये : मैं विदेश नीति के बारे में इतना ही कहना चाहता हूं कि जिस देश की नीति मानव जाति के कल्याण और राष्ट्र हित, दोनों में समन्वय स्थापित करके नहीं चलाई जाती है वह कभी सफल नहीं हो पाता है और न हो पाएगा।

तिब्बत के बारे में मास्को में दो साल पहले रूसी नेताओं से मेरी बातचीत हुई थी। अब की बार भी हुई है। धीरे-धीरे अब वे लोग समझ रहे हैं कि तिब्बत में चीन के द्वारा जो किया जा रहा है, वह मानव अधिकारों की हत्या है। अभी भी तिब्बत की स्वतंत्रता को कबूल करने की बात यह सरकार करने के लिए तैयार नहीं है। जब रूस की नीति बदलेगी तब शायद ये लोग सोचेंगे। लेकिन मेरा अपना खयाल है कि तिब्बत के बारे में अगर पहले से इनकी राय स्पष्ट होती तो आज रूस की जनता में भारत के प्रति जो सद्भावना है उसका इस्तेमाल करके चीन के आक्रमण को रोकने के काम में रूस की सक्रिय सहायता हम लोगों को और ज्यादा मिल सकती थी। लेकिन रूसी जनता के मन में जो सद्भाव है भारत के प्रति उसका यह अयोग्य और नालायक सरकार

[श्री मधु लिमये]

फायदा उठाने की स्थिति में नहीं है क्योंकि इनकी कोई दूर दृष्टि नहीं है। तिब्बत के बारे में ताशकंद रेडियो से आजकल खबरें निकल रही हैं और वहां चीन के द्वारा जो अत्याचार किये जा रहे हैं, उसकी आलोचना की जा रही है। लेकिन अभी भी सरकार तिब्बत के बारे में इसकी जो पुरानी सड़ी गली नीति है उसके ऊपर पुनर्विचार करने के लिए तैयार नहीं है।

उसी तरह सीमाओं के बारे में यहां कई बार बहस हुई है। पाकिस्तान के बारे में बहस हुई है। मैं इस सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं कि पाकिस्तान और हिन्दुस्तान जैसे साधारण दो पड़ोसी होते हैं उस तरह के दो पड़ोसी नहीं हैं। इनके रिश्ते साधारण पड़ोसियों के बीच में जो रिश्ते होते हैं उसकी तरह के न होने के कारण इनके प्रश्नों को एक एक करके अलग-अलग हल नहीं किया जा सकता है। हम लोगों ने देखा कि नेहरू-लियाकत करार हुआ और यह कहा गया कि शान्ति का युग शुरू हो गया है। लेकिन वह कहां गया? उसके बाद नून-नेहरू करार हुआ, सिंधु नदी के पानी के बंटवारे के सम्बन्ध में करार हुआ, कच्छ के बारे में करार हुआ और फिर ताशकंद करार हुआ। लेकिन हमने हमेशा देखा है कि दो तीन महीने तक तो ये खूब शान्ति के गीत गाते हैं और कहते हैं कि यह चार्टर आफ़ पीस है, लेकिन उसके बाद फिर तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, गोलीबारी शुरू हो जाती है और फिर वही स्थिति—या उससे भी खराब स्थिति—उत्पन्न हो जाती है।

इस सरकार को अभी फ़ैसला करना है कि पाकिस्तान के साथ अलग-अलग सवालों पर विचार उनको हल नहीं किया जा सकता है। सभी सवालों पर एक-साथ विचार हो, जिससे एक सुरक्षा नीति, एक विदेश नीति और एक यातायात और विकास के बारे में नीति निर्धारित हो सके। उसके साथ एक-एक सवाल को अलग अलग बातचीत कर के हल निकालने की जो कोशिश है, वह कभी सफल नहीं होगी।

जब पाकिस्तान के साथ हमारे रिश्ते खराब होते हैं, तो हमको खान अब्दुल गफ्फ़ार खां याद आते हैं; हमको याद आता है कि पूर्वी बंगाल की स्वायत्तता को कुचला जा रहा है, लेकिन जब ताशकंद करार होता है, तो हम पख्तूनिस्तान की जनता को भी भूल जाते हैं और पूर्वी बंगाल की आज़ादी को भी भूल जाते हैं। इस तरह की मौकेबाज़ी और अवसरवादिता की नीति को समाप्त कर के सरकार उन पुराने वादों और अभिवचनों के बारे में, जो कि हमने बादशाह खां को दिये, और इस बारे में हमारा जो दायित्व है, उसके बारे में हमेशा के लिए एक निश्चित और ठोस नीति बनाए और उस पर अमल करे।

हमको ऐसा लगता है कि विनोबा भावे ने तो भूदान की चर्चा आन्तरिक भूमि समस्या को हल करने के लिए की थी, लेकिन उनके विचारों का असर इस सरकार पर इतना ज्यादा हुआ है कि यह चीन और पाकिस्तान के साथ एकतरफ़ा भूदान और ग्रामदान चला रही है। यह सरकार अपनी भूमि देती जाती है, अपने ग्राम देती जाती है। इस सरकार के द्वारा कभी यह दृढ़ संकल्प नहीं किया गया है कि हमारी भूमि पर जो आक्रमण करेगा, उसका हम डट कर विरोध करेंगे।

मैं सरकार को कहना चाहता हूं कि हमेशा दूसरों के द्वारा पकाए जाने वाले सवालों पर ही अपनी राय देने में बुद्धिमानी नहीं है। रोडेशिया का सवाल है, दक्षिण अफ्रीका का सवाल है, मोज़म्बीक और अंगोला का सवाल है। आज भी पुर्तगाल के जेलों में हमारे दो देशभक्त सड़ रहे हैं। उनको छुड़ाने के लिए सरकार के द्वारा कोई प्रबन्ध नहीं किया गया है। बल्कि इनके पास जो पुर्तगाल के कैदी थे, उनको इन्होंने पहले ही बिना-शर्त छोड़ दिया। साम्राज्यवाद-विरोध की हमारी जो नीतियां हैं, उनको रोडेशिया, दक्षिण अफ्रीका, मोज़म्बीक और अंगोला में चालू करने के लिये सरकार के द्वारा कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। मैंने सुना है कि दक्षिण अफ्रीका के कुछ

प्रतिनिधि हिन्दुस्तान में आए थे। मैं सरकार से यह जानना चाहूंगा कि क्या इन लोगों की मदद करने के लिए उसने कोई निश्चय किया है।

रोडेशिया में जो अल्पसंख्यक सफ़ेद लोगों की तानाशाही हुकूमत है, उसको बातचीत के ज़रिये खत्म नहीं किया जा सकता है। अब वहां सशस्त्र संघर्ष का ज़माना आया है और इस बारे में हिन्दुस्तान को भी अपना दायित्व पूरा करना है। इस लिए मैं यह कहूंगा कि अपनी विदेश नीति के बारे में यह सरकार सोचे।

जहां तक आणविक हथियारों का सम्बन्ध है, मैं आज यह नहीं कह रहा हूं कि आज हम आणविक हथियार बनाने की स्थिति में हैं या हमको इन हथियारों का तत्काल निर्माण करना चाहिए। लेकिन मैं यह ज़रूर कहुंगा कि जिस तरह मास्को संधि पर हस्ताक्षर करने में इस सरकार की ग़लती हुई, उसी तरह की ग़लती वह दबाव में आ कर फैलाव रोकने वाली संधि के बारे में ज़रूर करती; अगर इसने आज तक ऐसा नहीं किया है, तो यह अपनी ताकत के कारण नहीं, बल्कि चूंकि रूमानिया और दूसरे कई देश इस नीति का डट कर विरोध कर रहे हैं, इस लिए इसकी हिम्मत हो रही है, वर्ना यह अपने अधिकारों को बेच डालती, मेरे मन में यह शक है।

मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आणविक हथियारों का आज ही निर्माण किया जाये। मैं चाहता हूं कि हमारे इस अधिकार को आने वाली पीढ़ी के लिए सुरक्षित रखा जाये, जब कि हमारे देश की आर्थिक और औद्योगिक स्थिति सुधरेगी और हमारे यहां वैज्ञानिक प्रगति हो जायेगी। इसलिए हम अपनी आने वाली पीढ़ी को बांधना नहीं चाहते हैं कि देश की रक्षा के लिए वह क्या-क्या कदम उठाए।

निश्शस्त्रीकरण के प्रश्न पर ध्यान देते हुए इन्दिरा गांधी की सरकार को यह भी कोशिश करनी चाहिए थी कि दुनिया से ग़रीबी को मिटाने के लिए जानसन, कोसिजिन और दूसरे देशों के मुतसद्दियों को एक जगह पर लाया जाता। लेकिन इधर पंद्रह बीस साल से हिन्दुस्तान विदेश नीति के क्षेत्र में कोई पहल नहीं कर रहा है। शुरू के दो तीन सालों में इस तरह के कुछ पग उठाए गए थे। 1947 में हिन्देशिया के प्रश्न को उठाया गया था और यहां पर एशियन सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसमें तिब्बत आया था। शुरू के इन दो तीन कामों को छोड़ कर इधर पंद्रह सालों में हिन्दुस्तान के द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में किसी भी तरह की पहल करने का काम नहीं किया गया है। इसी लिए इस सरकार की विदेश नीति, सुरक्षा नीति, औद्योगिक और आर्थिक नीति, राजनीति, संविधान, कानून और ग़ैर-कांग्रेसी सरकारों के प्रति इसकी नीति, इन सब नीतियों के खिलाफ़ यह प्रस्ताव है।

सब से बड़ा सवाल खेती का है। 1947 के बाद खेती के बारे में इस सरकार ने जो उपेक्षा की नीति अपनाई है, उसकी वजह से एक बुनियादी चीज़ के बारे में—अनाज के बारे में—हमारा देश आत्मनिर्भर होने के बजाय आज विदेशियों की तरफ़ ताकता रहता है। जब कभी स्वेज़ का मामला आता है, या कोई और मामला आता है, तो हमारे मन में हमेशा यह चिन्ता रहती है कि अनाज ले कर जो जहाज़ आ रहे हैं, वे आ पायेंगे या नहीं। 1950–51 में जहां हम 20 लाख टन अनाज मंगाया करते थे, वहां पिछले वर्ष हम को अमरीका और दूसरे देशों से 110 लाख टन अनाज मंगाना पड़ा। इसका कारण यह है कि लगातार इस सरकार के जो खाद्य मंत्री और खेती मंत्री रहे हैं, उन्होंने इस मामले को हल करने की कोशिश नहीं की। रफ़ी अहमद किदवई के बाद पाटिल साहब मंत्री बने। मुझे याद है कि मंत्री बनने के पश्चात् सब से पहले उन्होंने अफ़सरों की सभा बुला कर उनसे यह निवेदन किया था कि अब मैं खेती मंत्री बना हूं, मुझे ज़रा समझाइये कि खरीफ़ और रबी क्या बला है। इस तरह के कृषि पंडितों को खेती मंत्री बनाया जाता है।

[श्री मधु लिमये]

उसके बाद खेती की समस्या को हल करने के लिए उन्होंने हिन्दुस्तान में कोशिश नहीं की; वह खेती की समस्या हल करने के लिए वाशिंगटन चले गए। वह चाहते थे कि वाशिंगटन में इस समस्या का हल निकाला जाये। उनका इंगलैंड में 1961 में दिया गया भाषण मेरे पास है, जो हिन्दुस्तान के कई अखबारों में प्रकाशित हुआ था। उन्होंने कहा था कि अब हमारे सामने समस्या अधिक अनाज पैदा करने की नहीं है; हिन्दुस्तान में अनाज की समस्या को तो मैंने हल कर दिया है, अब इतना अनाज पैदा होने लगा है कि उसको रखें कहां, यह समस्या अब हमारे सामने आने वाली है और इसलिए मैं व्यापारिक फ़सलों की पैदावार पर ज्यादा ज़ोर देने वाला हूं।

खेती को प्रोत्साहन देने के लिए कई गैर-कांग्रेसी सरकारों ने एक सही कदम उठाया और लगान माफ़ कर दिया। अभी मैं कलकत्ते गया था। मैंने वहां पर पश्चिमी बंगाल सरकार का नया बजट देखा। उसको लगान से साढ़े छः करोड़ रुपये की आमदनी है, लेकिन वह लगान वसूल करने के लिए पांच करोड़ रुपये से अधिक खर्च कर रही है। लगान से आमदनी है साढ़े छः करोड़ और उसको वसूलने का खर्च है पांच करोड़। तो केवल डेढ़ करोड़ रुपया प्राप्त करने के लिए छोटे किसानों पर इस तरह के कर लगाए जा रहे हैं। कुछ राज्य सरकारों ने फ़ैसला किया कि हम इनको खत्म करेंगे। उड़ीसा और बिहार की राज्य सरकारों ने ऐसा किया। लेकिन इस पर हमारे वित्त मंत्री नाराज़ हो गए। जब लगान-माफ़ी का प्रस्ताव आया, तो उन्होंने उसका विरोध किया। खेती को प्रोत्साहन देने के लिए यह आवश्यक है कि छोटे किसानों पर लगान आदि जो टैक्स है, उनको खत्म करके सब से पहले सिंचाई का इन्तज़ाम किया जाये। जब तक सिंचाई का इंतज़ाम नहीं होता है, आप बीज की बात करो, उर्वरक की बात करो; यह भी चीजें जरूरी हैं लेकिन सिंचाई के बिना हिन्दुस्तान की खेती नहीं सुधर सकती। इनके पहले जो खाद्य मंत्री थे वह जानते थे कि तामिलनाड में और आन्ध्र में सिंचाई के बारे में कुछ तरक्की हुई है तो उनके दिमाग में हमेशा उर्वरक की समस्या थी। लेकिन वह भूल जाते हैं कि बाकी राज्यों में सब से बड़ी समस्या सिंचाई की है और छोटे सिंचाई के द्वारा, ट्यूबवेल के द्वारा या डीज़ल इंजिन या बिजली के मोटरों के द्वारा जब तक सिंचाई का प्रबन्ध नहीं किया जाता है, खेती की समस्या हल नहीं होगी।

खेती के साथ-साथ अध्यक्ष महोदय, जुड़ा हुआ सवाल है सामाजिक बराबरी का, सामाजिक एकता का जिसके बारे में इस सदन में पचासों दफा मैंने बहस उठाई थी। पिछले 20 सालों में पिछड़े वर्ग के बारे में; हरिजन और आदिवासियों के बारे में इस सरकार की जो नीति रही है वह बिलकुल गलत रही है। गृह मंत्री के द्वारा परिपत्र जारी किया गया कि सरकारी नौकरियों में लोक-संख्या के अनुपात में इनको नौकरियां मिलेंगी। हमारे सामने बैकवर्ड क्लासेज़ कमीशन की, शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज़ कमीशन की रपट आती है। हमको कभी-कभी मौका भी नहीं मिलता है, अब की बार तो थोड़ी बहुत बहस उस पर हुई और हम लोगों ने देखा कि जहां 18 प्रतिशत इनको नौकरियां सभी वर्गों में मिलनी चाहिए थीं, पहले वर्ग में मुश्किल से सवा प्रतिशत नौकरी इनको मिली है जबकि मिलनी चाहिए 18 प्रतिशत। दूसरे वर्ग में साढ़े तीन प्रतिशत से अधिक नौकरी इनको नहीं मिली है। तीसरे वर्ग में सात प्रतिशत और बड़ी उदार होकर यह सरकार कहती है कि चपरासियों और भंगियों की नौकरियों में आप लोगों को लोक-संख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व हम देंगे। वहां 17–18 प्रतिशत के लगभग है। तो इस सरकार के रहते हुए हिन्दुस्तान के जो आदिवासी हैं, हिन्दुस्तान के जो हरिजन हैं, हिन्दुस्तान के जो पिछड़े हुए लोग हैं उनकी तरक्की के लिए कोई कदम नहीं बढ़ाया गया।

अंत में सब से जुड़ा हुआ सवाल जो नागा प्रदेश, मिजो और पहाड़ी इलाकों का सवाल आया है, कल गृह मंत्री जी ने विरोधी दलों को दावत दी है लेकिन अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि सरकार जब नीति की घोषणा करती है तब तो विरोधी दलों से सलाह मशविरा नहीं करती है, लेकिन जब मामला उलझ जाता है, जब इनके हाथ फंस जाते हैं तो उसको निकालने के लिए और बुराई दूसरों के ऊपर थोपने के लिए विरोधी दलों को बुलाते हैं। इसलिए कम से कम मेरे दल की ओर से मैंने फैसला किया है कि इस काम में इनकी सहायता करने के लिए मैं नहीं जाने वाला हूं।

अध्यक्ष महोदय, सारी समस्याओं को इन्होंने उलझाया। राज्य पुनर्रचना के बारे में तो मैं एक ही वाक्य कह कर खत्म करने वाला हूं कि किसी भी देश में 25 साल में, 50 साल में एक दफा राज्यों की पुनर्रचना होती है ठोस सिद्धांतों को ले कर, लेकिन यह अभागा ऐसा देश है कि इस देश की राज्य-पुनर्रचना कभी खत्म ही नहीं होती। हर साल चलती रहती है। पिछले वर्ष हमको लगा कि अब पंजाब का बंटवारा हो गया, अब राज्य-पुनर्रचना खत्म होगी। लेकिन अब आसाम का मसला आया है। हिन्दुस्तान में राज्य-पुनर्रचना का काम कभी खत्म होने वाला नहीं दिखता जो कि वास्तव में 50 साल में कहीं एक ही दफा होना चाहिए ठोस और निश्चित सिद्धांतों के आधार पर। लेकिन वह यहां अभी तक पूरा नहीं हुआ।

इसलिए अध्यक्ष महोदय, इन सारी नीतियों को ले कर इस सरकार की जो असफलता रही और लोकतंत्र का गला घोंटने का इन्होंने जो काम किया है इसके लिए यह निन्दा प्रस्ताव, अविश्वास का प्रस्ताव हम लोग लाये हैं। आपके मार्फत मैं सदन का आह्वान करना चाहता हूं कि इस प्रस्ताव का समर्थन करके इनकी गर्दन पकड़ कर इस अयोग्य और नालायक सरकार को निकाल दें।

MR. DEPUTY-SPEAKER : Motion moved :

"That this House expresses its want of confidence in the Council of Ministers."

श्री शशिरंजन (पपरी) : उपाध्यक्ष जी, आज इस अविश्वास के प्रस्ताव को लाने का मुख्य कारण पश्चिम बंगाल में जो सरकार बदली गई है, वह था। लेकिन हमारे मित्रों ने, जिन लोगों ने अविश्वास का प्रस्ताव रखा है, उनके पास शायद इतना काफी मसाला नहीं मिला ताकि वह पश्चिम बंगाल के गवर्नर को या वहां जो सरकार बदली गई है उसके बारे में कुछ कह सकें तो उन्होंने एक सारा लम्बा चौड़ा विस्तारपूर्वक, जो चीजें हो चुकी हैं उनको फिर से दोहराने का प्रयास किया है। जो बातें लिमये साहब ने कही है वह बातें कई बार अविश्वास के प्रस्ताव जो इस सदन में आये हैं उनमें दोहरायी जा चुकी हैं और कोई नई बात ऐसी उन्होंने नहीं कही है। एकाध बात उन्होंने नई जरूर कही है। उन्होंने कांग्रेसी सरकार के बारे में कहा है। पर दुख है कि आज कई प्रांतों में जो गैर-कांग्रेसी सरकार है उसके बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा क्योंकि वह जानते हैं कि गैर-कांग्रेसी सरकार जहां है वहां जो कांग्रेसी सरकार थी उससे भी बदतर हालत है। आज अफसोस है, स्वर्गीय लोहिया जी हैं नहीं। नहीं तो वह इस बात को कहने को मजबूर हो गए थे कि इधर और उधर में कोई फ़र्क नहीं रहा। लेकिन आज वह हैं नहीं। आज वह हमारी इस बात की पुष्टि करते।

एकाध बात की ओर मैं पहले ध्यान दिलाना चाहता हूं। फिर मैं वेस्ट बंगाल की ओर आऊंगा। इन्होंने कई चीजों के बारे में, मूल्यों के बारे में कहा है। कई प्रदेशों में गैर-कांग्रेसी सरकार है। उनके ऊपर यह दायित्व है कि वह वहां के मूल्यों का निर्धारण करें, वहां के मूल्यों का नियंत्रण करें। पर दुख है कि वहां के मूल्यों का नियंत्रण होने के बजाय वहां मूल्य बढ़ते जा रहे हैं। इनको मालूम होगा कि जब वहां कांग्रेसी सरकार थी तो जो

▽

[श्री शशि रंजन]

चीजें जिस भाव में मिल रही थीं आज उससे तिगुने भाव पर वहां वह चीजें मिल रही हैं।

एक माननीय सदस्य : और तुम्हारे राज्य में क्या हो रहा था ?

श्री शशि रंजन : आप तो कांग्रेसी सरकार का दोष देते हैं। आप जरा गैर-कांग्रेसी सरकार के बारे में सुनिए।

एक बात इन्होंने कही कि बहुत से रोजगारों में या बहुत से गलत कामों में गलत ढंग के पैसे में मंत्रियों का हिस्सा होता है। मैं इस बात पर बहुत दिनों से जानना चाहता था कि मुझे कुछ पता चले। मेरे मित्रों के बारे में जो इस तरह के मंत्री हैं कि उनका कुछ हिस्सा है या नहीं लेकिन मुझे उसका कुछ पता नहीं चला। पर जब गैर-कांग्रेसी सरकार मेरे बिहार में बनी और मैंने कुछ मंत्रियों के बारे में जांच की तो मुझे विश्वास हो गया कि सचमुच में मंत्रियों का हिस्सा होता है। कांग्रेसी के बारे में तो मुझे पता नहीं चल सका लेकिन गैर-कांग्रेसी मंत्रियों के बारे में पता चला है। खैर, यह सब बातें हैं छोटी मोटी। हम समझते थे कि हमारे मित्र वेस्ट बंगाल के बारे में विशेष तौर से उस पर विचार करेंगे, उनकी तवज्जह उस पर जायगी लेकिन वह न करके एक लम्बी चौड़ी बात उन्होंने की है। वेस्ट बंगाल के बारे में मैं कहना चाहता हूं, मुझे अक्सर जो आई० सी० एस० आफिसर बड़े बड़े ओहदे पर रखे जाते हैं उनसे कुछ असंतोष सा रहता था।

15 Hrs.

मैं समझता था कि हमारे संविधान में जो सोशलिज्म है, हमने जिस समाजवाद को संविधान के जरिये माना है, जिस समाजवाद को हम इस संविधान के जरिये अपने देश में लाना चाहते हैं, उसको लाने का मुख्यतर भार उन बड़े अफसरों, आई० सी० एस० के लोगों पर है, लेकिन मैंने देखा कि जब तक वे लोग अपने ओहदों पर बने रहते हैं, तब तक तो कुछ नहीं पता वे उसको सही रूप में लाने की कोशिश करते हैं या नहीं, लेकिन जिस दिन वे रिटायर होते हैं या आई० सी० एस० के अपने ओहदों से हटते हैं तो पहला काम यह करते हैं कि स्वतन्त्र पार्टी में चले जाते हैं। मुझे इस बात पर शक होने लगा था कि ये बड़े बड़े ओहदे वाले आई० सी० एस०, जिनके ऊपर हम अपना पूरा विश्वास रखते हैं कि वे समाजवाद को इस देश में चलायेंगे, जिस संविधान में समाजवाद को हमने मंजूर किया है, उसको वे कार्यान्वित करेंगे, लेकिन वे नहीं करते हैं और उनका उसमें विश्वास नहीं है और यही वजह है कि रिटायर होने के दूसरे दिन ही वे स्वतन्त्र पार्टी में चले जाते हैं।

लेकिन आज मुझे इस बात की खुशी है कि एक ऐसा आई० सी० एस० अफसर जो बंगाल का गवर्नर हो कर गया है...

श्री समर गुहा (कन्टाई) : लज्जा की बात है। नेशनलिस्ट नहीं मिला, तभी ब्यूरोक्रेसी को दे दिया।

श्री शशि रंजन : मैं उनकी तारीफ़ करता हूं, उन्होंने अपनी बुद्धि और अपनी काबलियत का पूरा पूरा परिचय दिया है और उन्होंने बजाय इसके कि वहां पर प्रेज़िडेन्ट रूल करें, वहां एक प्रजातान्त्रिक सरकार बनाने का मौका दिया है।

आज के स्टेट्समैन ने इस बात को कहा है कि वहां प्रेज़िडेन्ट रूल होता तो अच्छा था। मुझे अफसोस हुआ कि उन्होंने प्रेज़िडेन्ट रूल को एक प्रजातान्त्रिक राज्य से बेहतर समझा। मुझे पता नहीं कैसे उन्होंने इसको बेहतर समझा।

अब मैं इस संविधान के बारे में एक-दो बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। आम तौर पर लोग कहते हैं कि गवर्नर एक कांस्टीचूशनल हेड होता है, उसका कोई फंक्शन नहीं है। लेकिन अगर हम धारा 163(2) को पढ़ें तो हमें पता चलेगा—

"If any question arises whether any matter is or is not a matter as respects which the Governor is by or under this Constitution required to act in his discretion, the decision of the Governor in

his discretion shall be final, and the validity of anything done by the Governor shall not be called in question on the ground that he ought or ought not to have acted in his discretion."

अब मैं दूसरा क्लाज़ पढ़ना चाहता हूं--

"But the Governor is not going to be a mere figure-head. If the Governor were an active and good Governor, he could, by means of getting in touch with the opponents of the party in power, reconcile them to a good number of measures and generally make the administration run smoothly."

इस के बारे में अम्बेदकर साहब ने कांस्टीचूएन्ट असेम्बली में कहा है ।

I would like to read a few lines of that—

"As Dr. Ambedkar explained, in discussing the position of the Governor, the distinction should be borne in mind between 'functions' and 'duties'. While the Governor shall have no *functions* to discharge by himself, and would have no power to override the Ministry in any particular matter,—he would have the *duty* to advise the Ministry, not as the representative of any particular party, but of the people as a whole,—with the object of securing an impartial, pure and efficient administration."

इस मामले में गवर्नर ने पूरा-पूरा वही किया है जो हमारे संविधान में कहा गया है और कांस्टीचूएन्ट असेम्बली में जो भाव उस वक्त मेकर आफ दी कांस्टीचूशन-अम्बेदकर साहब ने, जिनको कुछ लोग मनु भी कहते हैं व्यक्त किये थे, उन्हीं भावनाओं के मुताबिक उन्होंने काम किया है ।

मैं एक-दो लाइन और पढ़ना चाहता हूं—

"Ultimately, of course, the Governor must take the advice given by his Ministers but the role of the Governor is not exactly that of a passive agent."

So, it is not exactly that of a passive agent. Here exactly he has not behaved like a passive agent.

उन्होंने अजय साहब को कहा कि आप जल्दी से जल्दी असेम्बली को बुलाइये । उन्होंने नहीं बुलाया, शायद वे बुलाते, लेकिन जब वह अपनी कैबिनेट में गये तो उन को याद आ गया कि बर्दवान में क्या हुआ, आसनसोल में क्या हुआ, हावड़ा में क्या हुआ, उस बेचारे ने सोचा पता नहीं बाद में मेरा क्या होगा, लिहाजा उस ने कह दिया कि 18 दिसम्बर से पहले नहीं बुलाऊंगा ।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : क्या नुक्सान हो जाता ?

श्री शशि रंजन : नुक्सान क्या हो जाता—

The Constitution specifically says that the Governor must not act as a passive agent. He must use his discretion in the smooth running of the Government and in the smooth running of the Government, he has acted.

इस लिये उन्होंने इस बात को समझा कि जरूरी है ताकि शासन व्यवस्था सुव्यवस्थित ढंग से और अच्छे ढंग से चले, ताकि वहां की जनता को मालूम पड़े कि वहां कोई शासन है—इसलिये उन्होंने इस को मुनासिब समझा कि वह अजय साहब को कहें कि विधान सभा को जल्दी से जल्दी बुलाइये—लेकिन अजय साहब mere puppet in the hands of a few न रहे ।

मैं अपने मित्रों को एक बात और बता देना चाहता हूं—आज अभी सवा तीन बजा है, नई सरकार को बने हुए काफी घन्टे हो गये हैं, लेकिन कोई भी ऐसा वाक्या वहां नहीं हुआ है, जिससे कि यह जाहिर हो कि वहां की जनता यह चाहती है कि यह सरकार न रहे ।

श्री स० मो० बनर्जी : पूरी हड़ताल है . . . . (**व्यवधान**) . . . . . .

कुछ माननीय सदस्य : बिल्कुल नहीं ।

श्री शशिरंजन : मेरे पास अभी ढाई बजे तक की खबर है । उपाध्यक्ष महोदय, सिवाय इस के कि 50-60 आदमियों का एक जलूस

[श्री शशिरंजन]

निकला और कुछ थोड़ा-बहुत हँगामा हुआ, इसके अलावा कुछ नहीं हुआ और वे सब भी अपने-अपने घर चले गये । वहां कोई ऐसा वाक्या नहीं हुआ, जिसका कि ये लोग बहुत बड़ा नक्शा पेश करते थे—वहां घर-घर में, गली-गली में खून बहेगा ।

अब मैं एक बात और कहना चाहता हूं । मैं आपको तवज्जह थोड़ा बिहार की तरफ ले जाना चाहता हूं । जो बात हरियाणा में हुई, जो बात पंजाब में हुई, मैं प्रधान मंत्री जी से बहुत साफ अल्फाज में कहना चाहता हूं कि उन को बिहार के बारे में भी बहुत गम्भीरतापूर्वक सोचना पड़ेगा । क्योंकि बिहार में आज कोई शासन नहीं है । मैं उस की वजह बताना चाहता हूं—बिहार के चीफ मिनिस्टर आज 10 दिन से बिहार में नहीं हैं, पहले इन्दौर में थे, फिर दिल्ली में थे और अब कलकत्ते में थे । सन् 1952 से आज तक की बात मैं कहता हूं कि कोई भी चीफ मिनिस्टर 10-12 दिनों तक राज्य से बाहर नहीं रहा । अगर ये कह दें कि कोई भी चीफ मिनिस्टर लगातार 12 दिन तक बाहर रहा है तो मान लूं कि ये सच्चे हैं ।

SHRI BAL RAJ MADHOK (South Delhi) : Don't tell us wrong things. The Chief Minister of Bihar was in Bihar. He went with me in the same plane. Only yesterday, he went to Calcutta. (*Interruptions*).

मैं नहीं कहता कि वहां कांग्रेस की सरकार बने लेकिन यह मैं जरूर कहूंगा कि वहां कोई अच्छी सरकार बननी चाहिये और वह सरकार आज बिलकुल निकम्मी सरकार है । वहां के जिलों में..... (**व्यवधान**)

श्री शशिरंजन : जरा शान्त होकर सुन लीजिये..... (**व्यवधान**)

SHRI S. M. BANERJEE : On a point of order.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Is it a point of order or an interruption ?

SHRI S. M. BANERJEE : I rise on a point of order. My point of order is this. During the discussion here, personalities should not be brought..(*Interruption*). Merely because the Chief Minister went out of Patna...

SHRI RANDHIR SINGH (Rohtak) : What is the point of order here ? (*Interruption*).

SHRI S. M. BANERJEE : Mr. Shashi Ranjan is a good friend of mine...

MR. DEPUTY-SPEAKER : What is the point of order ? (*Interruptions*).

SHRI SHEO NARAIN (Basti) : Let him come out with his point of order.

SHRI S. M. BANERJEE : If they go on shouting like this, how can I speak ? Will you please ask these bullies to keep quiet?

MR. DEPUTY-SPEAKER : Order, order.

SHRI SHASHI RANJAN : I obey you, hundred per cent, Sir.

SHRI S. M. BANERJEE : My point of order is this. In the past during many debates, if anybody wanted to discuss the conduct of any Chief Minister or even an ex-Chief Minister, even of thieves like Shri Biju Patnaik, the Chair did not allow him; we were not allowed to discuss it. Here, Mr. Shashi Ranjan, a veteran Parliamentarian, mentioned Mr. Ajoy Mukherjee as a tool in the hands of the other Ministers. I had tolerated that. Today he is an *ex*-Chief Minister. But Mr. Maha Maya Prasad Sinha is still a Chief Minister and with all their bullying tactics, he is going to remain there till Mr. Chavan murders him also....(*Interruptions*).

AN HON. MEMBER : What is his point of order ?

SHRI S. M. BANERJEE : My point of order is whether it is open to a Member to mention the...(*Interruptions*).

MR. DEPUTY-SPEAKER : He may resume his seat. I have understood him. But here it is a statement that the hon. Member is making on his own information. He is not making any allegation...

SHRI S. M. BANERJEE : He is casting aspersion of the Chief Minister.

MR. DEPUTY-SPEAKER : No, no. He may resume his seat. There is no point of order.

The hon. Member may continue his speech.

श्री शशिरंजन : मैंने सिर्फ यही कहा कि आज तक कोई भी चीफ मिनिस्टर लगातार दस दिनों तक अपनी स्टेट से बाहर नहीं रहा ।

श्री स० मो० बनर्जी : प्रधान मंत्री आप के बराबर देश के बाहर कई-कई दिनों तक घूमते रहते हैं ।

SHRI J. B. KRIPALANI (Guna) : How does it matter if Mr. Maha Maya Prasad Sinha was absent for ten days ? Here, the Central Ministers remain absent for one month and more.

SHRI SHASHI RANJAN : I do not hold any brief for these Ministers who have remained absent for ten days. I equally decry those Ministers who remain absent, whether for ten days or one month.

खैर, मैं दूसरी बात यह अर्ज कर रहा था कि यह 6-7 महीने इन लोगों को हुए हैं सरकार बनाये हुए । इन 6-7 महीने में बिहार में तीन बड़े-बड़े रायट्स हुए हैं । माइनारिटी और मेजौरिटी कम्युनिटी के तीन बड़े-बड़े रायट्स हुए हैं····· (**व्यवधान**)

SHRI NAMBIAR (Tiruchurappalli) : Are we discussing Bihar now, Sir ?

SHRI VASUDEVAN NAIR (Neeswade) : The Congress was behind the riots.

SHRI KANWAR LAL GUPTA (Delhi Sadar) : The point of order is this. The Punjab Ministry has fallen because 17 MLAs have defected from the United Front and the Congress has assured their support to these defectors... (*Interruptions*).

SHRI M. L. SONDHI (New Delhi) : They are habitual murderers.

MR. DEPUTY SPEAKER : The hon. Member may now continue his speech.

श्री शशिरंजन : उपाध्यक्ष महोदय, तीन बड़े-बड़े रायट्स हुए, छोटे-मोटे रायट्स नहीं हुए । एक जिले के रायट के समय वहां की पीस कमेटी का चेअरमैन मुझे सब पार्टियों ने और सरकार ने मिल कर बनाया । मैं इन रायट्स एफेक्टेड एरियाज को देखने गया । जिन्होंने वहां सफर किया है एक कम्युनिटी के वह लोग एक कैम्प में थे और दूसरी कम्युनिटी के लोगों ने जो सफर किया है वह दूसरे कैम्प में थे । जब मैं वहां गया तो मैंने कहा कि मैं न सरकार की बात सुनूंगा और न ही मैं किसी पोलिटिकल पार्टी की बात सुनूंगा । मैं वहां जो उस कैम्प में रहते हैं मैं उन के मुंह से उन की बात सुनना चाहता हूं । क्या तकलीफें हैं, क्या बातें हैं, मैंने उन से पूछा कि इस कैम्प में तुम कितने आदमी हो । उन्होंने कहा कि 1000 । मेरे साथ पीस कमेटी के दूसरी पार्टी के जो सदस्य थे वह उन को बराबर उकसाते रहते थे । उन्होंने कहा कि नहीं साहब आप एक हजार नहीं हैं आप 1600 हैं । मैंने कहा कि जो रहने वाले हैं वह कहते हैं कि 1000 हैं और तुम कहते हो कि वह 1600 हैं तो यह क्या बात हुई ? उन्होंने कहा कि नहीं साहब सरकारी रिपोर्ट देखिये । मैं ने कहा कि भाई सरकार की जो मिनिस्टरी है वह तुम्हारी पार्टी की है । रेवेन्यू मिनिस्टर तुम्हारी पार्टी के हैं वह जितना चाहे लिख दें । इस तरह की बातें कहना और इस तरह से उकसाना यह चीजें उनकी तरफ से की गईं । मैं 7 दिनों के बाद जब उन के पास गया तो मैं ने कहा कि भाई तुम्हें क्या तकलीफ है तुम लोग अपने घरों को चले जाओ । उन्होंने कहा कि हमारा घर टूट गया है, हमारा घर जल गया है आप उस को बनवा दीजिये । मैंने उन को कहा कि तुम्हारा घर फूंस का था, मैं उस को अच्छे तरीके से बनवा दूंगा । दूसरी पार्टी ने कहा कि नहीं साहब उन का घर तो ऐस्बैस्ट्स का बनना चाहिये····· (**व्यवधान**) काइंड्ली लिसिन मी । मैं कह रहा था कि मैं ने उन से कहा कि आप अपने घरों में जाइये । उन्होंने कहा कि

[श्री शशिरंजन]

मैं जाने को तैयार हूं। दूसरी पार्टी के जो लोग थे उन्होंने कहा कि घर एस्वेस्ट्स का बनवा दीजिये। किसी ने कहा कि ईंटों का बनवा दीजिये। सरकार तैयार हो, बिहार सरकार से पैसे लेकर मैं बनवा दूंगा। कहा गया कि नहीं आप सेंटर से पैसे लेकर आइये। अब सेंटर कोई मशीन नहीं है जहां से पैसा निकाल कर लेते चले जाओ। वह अपने घरों को जाने को तैयार थे लेकिन उन्होंने कहा कि उन की सिक्योरिटी का क्या इंतजाम होगा। मेरे पास साथ डाक्टर था, डाक्टर ने कहा कि जो भी सिक्योरिटी आप कहेंगे वह मैं उन को दूंगा और वह लोग तैयार थे लेकिन जो पार्टी इन्टेरेस्टेड है उस ने कहा कि नहीं आप मत जाइये और उन लोगों को जाने नहीं दिया गया। इस तरीके से एक अराजकता, एक कुशासन यह जो प्रदेशों में फैला हुआ है उस को दूर करना यह हम सभी लोगों का काम है और उस के लिये मैं सभी पार्टियों के लोगों से कहता हूं कि वह इस में हाथ बंटायें। इस में सभी पार्टियों की जवाबदेही है।

यह सब सोच कर के एक रास्ता निकालें। क्या हम चाहते हैं कि इसी तरह की सरकार चले? मुझे अफसोस है कि आज डा० लोहिया नहीं हैं। अगर लोहिया जी होते, और मैं उन के साथ घूमा होता, तो वह शत-प्रतिशत मेरे साथ इत्तफाक करते कि मैं बिलकुल ठीक कह रहा हूं..... (**व्यवधान**)। लोहिया जी के साथ मैं बहुत घूमा हूं। उन के साथ मेरा परिचय बीस वर्ष का था। मैं कहता हूं कि हम सब लोगों को, इस सरकार को, इस सदन को, आवश्यकता है कि हम सोचें। मैं यहां पर केवल गैर-कांग्रेसी सरकारों की बात नहीं कहता हूं। आज कोई भी ऐसी सरकार नहीं है, कोई शासन नहीं है, कोई प्रदेश ऐसा नहीं है, जहां पर जनता को, लोगों को मुनासिब दामों पर कोई चीज मिलती हो या जीवनोपयोगी सुविधायें मिलती हों। आज मिडल क्लास का आदमी सब से ज्यादा परेशानी में है, लेकिन उस की ओर किसी का ध्यान नहीं जाता।

इस लिये मैं इस सदन से कहना चाहता हूं कि वह गम्भीरता से सोचे। यह कोई लम्बी-चौड़ी बात नहीं है। आज श्री लिमये ने देश विदेश की बात कही। जब देश नहीं तो विदेश क्या, दुनिया क्या? पहले देश देखो फिर विदेश भी देखो। जब देश नहीं देखा तब विदेश क्या, अगल क्या, बगल क्या?

इन शब्दों के साथ मैं कहना चाहता हूं कि हम को इन सब बातों पर गम्भीरता से विचार करना चाहिये। इन पर रंज होने की आवश्यकता नहीं है। आज बंगाल में सरकार बदल गई, लेकिन वहां कोई कांग्रेस की सरकार तो बनी नहीं है। श्री पी० सी० घोष एक पुराने देश सेवक हैं, कांग्रेस के सेवक नहीं हैं, लेकिन देश सेवक हैं, जिन का बहुत बड़ा भाग है स्वतन्त्रता संग्राम में, आज वह मुख्य मंत्री हैं। इस लिये हम सब लोगों का फर्ज है कि उन के हाथ मजबूत करें और एक ऐसी सरकार दें ताकि बंगाल के लोग यह समझ सकें कि हमारा जीवन, हमारा धन सुरक्षित है और हमारा जीवन सुखी होता जा रहा है।

SHRI RANGA (Srikakulam): I am glad that my hon. friend Shri Madhu Limaye has broad-based his charges against Government and not confined himself mostly to the immediate crisis that has been created by Government through their action in West Bengal.

15.23 HRS.

[SHRI G. S. DHILLON *in the Chair*]

It was because we were afraid that this motion was being moved solely for the purpose of condemning this Government for what they had done in West Bengal that we were not in a position in the morning to associate ourselves with our colleagues in the Opposition.

SHRI VASUDEVAN NAIR: Then, the Orissa Government also will be dismissed.

SHRI RANGA: I am glad that this no-confidence-motion is placed before the House in the manner as it ought to be as a general motion.

SHRI RANDHIR SINGH: The Punjab Government has fallen. (*Interruptions*)

AN HON. MEMBER : They are disturbing all the non-Congress Governments.

SHRI M. L. SONDHI : My hon. friend does not have the courage to speak out; he shouts in the House, but outside the House he keeps silent.

SHRI RANGA : I look upon this motion as one that gives us an opportunity to express our no-confidence in the various policies and programmes and activities of this Government.

Let me take my stand as a kisan here in our country and in this House. Let us look at their food policy. Has it not been a failure ? Has it not been a self-confessed failure on the part of this Government that even after twenty years of the attainment of Swaraj we should still be dependent upon foreign imports of foodgrains to the extent of about 10 million tonnes every year. Is it not also a fact that in spite of these imports and the consequent pressure that is being brought down upon our kisans in regard to the prices that they should legitimately claim and obtain for their produce, they are not able to feed our people and our country, they are not able to control the prices for the consumers ? Is it not also a fact that as a result of the policies they have been pursuing, this country's food production is not progressing as well as it ought to in tune with the rise in our population ? So on that count we condemn this Government.

Is it also not a fact that in spite of the protests that our Party has been making for the past eight years against the zonal controls with compulsory procurement of foodgrains at uneconomical prices, this Government has been insisting upon maintaining these zonal controls, and not being satisfied with that, it has enforced district to district controls also in every State and in that way destroyed the economic unity of the country, converting it into only a district-based country and nothing more ?

My hon. friend, Shri Madhu Limaye, referred to the failure of the Government on the international front. Let me take this opportunity to place on record our protest against the visit that the Prime Minister made recently to Moscow ! For what purpose and on what occasion ? On the occasion of the 50th anniversary of their Communist Party, not of the Communist regime. If it was a matter of diplomatic courtesy, then the Prime Minister should have gone for the 50th anniversary of the Socialist Republic, not for their Party's 50th anniversary or golden jubilee or whatever it is. If they wanted to show their affinity with that regime, with that party, they could have sent their party chief, Shri Kamaraj, but not the Prime Minister. But why is it that they have done what they did ? Because they have got accustomed to hanging on to the apron-strings of Soviet Russia and her Communist Party. We condemn this Government on this score also.

15.27 Hrs.

[SHRI S. M. JOSHI *in the Chair*]

In regard to Government's policy on West Asia, even while Soviet Russia and America were busy persuading themselves and persuading the UAR to accept the existence of Israel, to accept a no-war proposition as between themselves, our Government was insisting in maintaining that Israel was the aggressor and that she should go back to *status quo ante*, thus blocking the way to recognition of the existence of Israel by the UAR and other Arab countries. What does that mean ? It means that we are more mad than Soviet Russia. While Soviet Russia is busy pursuing an independent policy recognising the changes in the situation there, we are hanging on to Soviet Russia's old policy. They have not taken the trouble to warn our Government of the kaleidoscopic changes in their own foreign policy before they take their own initiative, much so that while Soviet Russia is taking initiative in a liberal manner, we are hanging on to the old conservative political cloak of Soviet Russia which she has been shedding into the dust-bin. Therefore, on this count also, we express our want of confidence in the Government.

Then let us come to the general economic situation in the country. Recession is claiming more and more victims. Tens of thousands of industrial workers in every part of the country are becoming unemployed. When they cry for employment, there is no one to look after them, there is no one to heed their voice. More and more industrial plants are going slow, are obliged to go slow. While the Finance Minister says that he does not want any

[Shri Ranga]

deficit financing, the Minister of Industrial Development contends that deficit financing is inevitable and even advisable. All the time inflation is going on. The Nasik Press is busy, visibly or invisibly, admittedly or otherwise. It is busy producing more and more notes. In the name of relaxation of credit from the Reserve Bank and other scheduled banks, they are adding more and more to the circulation of money in our country in the hands of the industrialists and other people also. In spite of it, this recession is still there.

Do they propose to reduce the tax burdens? They want to raise them more and more. On top of it, the Finance Minister is going on admonishing the State Ministers who have had the moral courage and sympathy for the kisans to abolish or reduce land revenue. Is he going to the rescue at least of the famine-stricken people in our country, or the cyclone-affected people in Orissa, or the drought-affected people as in Orissa, Andhra, Bihar and other places? No. The Chief Ministers go on complaining that the Finance Minister here says that he has no money, he is not going to give them any kind of assistance or succour with the result they are not able to make their own plans in order to provide immediate relief for the semi-starved and near-starved masses of their own States. That is the parlous condition to which this Government has brought our country.

One would have thought they would have learnt their lessons after the results of the last election, and developed and devised a statesmanlike relationship between the Union Government and the State Governments, but how can anybody expect any kind of statesmanlike reorientation of policies from this Government, out-dated Government. It still hangs on like Methusela to its own power.

What is the position today? Just now, one of my friends comes and tells me that in Punjab also the Ministry is going to fall or has fallen, because there were defections. As I said yesterday, who is responsible for these defections, who if it is not these Congress gentlemen?

I now come to this immediate question of West Bengal. What is happening there? As I said yesterday—I make no apologies to anybody—I wanted the Bengal Ministry to be dismissed. For what reason? Not because it was playing the role of SVD. If it had played the SVD role of a non-partisan, non-Congress, democratic Government, providing honest administration, securing and assuring safety and law and order to the masses and industry and workers, certainly I would have continued to support it, as I am continuing, as we are continuing, to support the other SVD Governments. But most unfortunately for us and unwisely for those Communists in Bengal, the Marxists there thought that they could take law into their own hands, seize power or monopolise power for their own party use, and transform the SVD Government into a Communist Government. They made the mistake of thinking that here and now they could pursue their communist tactics. Hence arose Naxalbari, gherao. They took a long time to accept an iota of wisdom in order to give up that gherao. No wonder there has been a cry from the masses, there has been a disenchantment with that ministry. Therefore, I am not sorry, and indeed I am happy, that it has gone. But wait a minute.

What is it these people have done, and the Home Minister? Just as they have dismissed that Haryana Ministry and the legislative assembly, they should have dismissed this Assembly as well. Instead of that, they keep that legislature in being, then they pitchfork one of our friends to be the Chief Minister. It is a shameful act on the part of the Government. I am extremely sorry that one of my oldest colleagues, a colleague of my friend Acharya Kripalani also, for whom I have, and I had all this time, the greatest possible respect, for his political integrity should have allowed himself to be exploited by these Congress powermongers. He took the right and courageous step in resigning from the SVD Government. He came out; well and good. But why should he have allowed himself to be put into this unenviable position? It is not as if Chief Ministership is something new to him. He had been Chief Minister from the very beginning indeed, for about six to nine months. It was the intolerance of these congressmen and their passion and unquenchable desire for power that were responsible for his dismissal at that time. (*Interruption*). And unfortunately, he got into this unenviable position. What is the

responsibility of this Congress Government and the Union Government ? Is it right for them, and could it not have been proper for them to face this situation and ask their own Congress party to form a Ministry and then face the Legislative Assembly ? They did not have the moral courage to do that. Instead of that, they have pitchforked this gentleman and two or three of his colleagues, and tomorrow or the day after, I suppose there would be another 10 people marching towards the Governor only to take the oath of allegiance. And how many of them ? Only 17, in that Assembly of more than 200. These 17 are to form the Ministry. Does it not violate their political conscience ? Do they not realise what a political crime they have committed towards our democracy in our country in order to place political power in the whole of West Bengal in the hands of this tiny Trio ? Then they say, "we are going to support them." Yes; but they will pull the pulley and strings and these people will go on playing according to their tune ! And is this any service to democracy at all ? Therefore, I demand that this Government, if it were to have any kind of respect for democracy and decency, should dismiss this new Ministry and wait until the Assembly meets; let the Assembly express its view, and whomsoever it wants, let him become the Chief Minister. If, however, they think that the real, larger interests of the masses there could be better served by President's raj, let them be honest and have President's raj, if need be for six months, or even for one year; we do not mind that. Let there be that kind of rule. Let the people have that opportunity for thinking for themselves and then, thereafter, let there be a mid-term general election and let the people elect their own ministry.

It might be said by those friends, as the Haryana Governor was saying the other day and as the Home Minister also was saying, that just as it is not possible to have any kind of a decent group of people to form a majority in Haryana, it may not be possible to have a kind of democratic-minded majority group of parties or a regular party itself to provide a majority ministry in West Bengal. If that is so, why not they give consideration to the suggestion that I have been making for years : that in all such problem States as these, we should have an all-party government, all of them coming together, sharing power and working together and providing a pure government, a good government, an economical government and an honest government. That is what the people are hungering for and thirsting for. And my hon. friend Shri Mahamaya Prasad Sinha has been able to provide that kind of good government, an honest government, in Bihar. He has been able to tackle the situation, the hunger situation, well. (*Interruption*). If Congress Government had come in there, there would have been thousands of hunger or starvation deaths. (*Interruption*) . It is because my hon. friend Shri Mahamaya Prasad Sinha and his SVD Government had provided relief to the suffering people in that State. (*Interruption*). I know my friends over there are thirsting for power in Bihar also. They may possibly jockey themselves again into power in that State. Now, while that ministry is in power, can it be denied that they have provided famine relief to millions and millions of people, and thus prevented hunger deaths in that State ? Can anybody deny that ? Is it not a fact that on other occasions, not only there but also in Orissa and other places, whenever such famine relief had to be distributed, they used their own political agents and made political capital out of it, whereas on this occasion, Shri Mahamaya Prasad and his government have been able to give a good, decent administration ? It is that form of government that we want (*Interruption*).

Now, Sir, our difficulty is this. True, this Government has done the right thing in advising the Governor to dismiss that ministry which became only a Communist Government. But where is the guarantee that it is not going to play in other places the same kind of dirty trick that it has played in West Bengal, by pitchforking these three gentlemen into an alternative government ? From the impatience of these gentlemen I can see that they want to play the same sort of trick in Bihar as they have done today already in Punjab. They will play the same mischief in Orissa, in Uttar Pradesh and even in Madras. There are always Mir Jaffars and Jaichands to destroy Sirajuddin and Prithviraj on one side. Many of these friends have been experts in discovering these people, fashioning them into political puppets and exploiting them for their own purpose. That is what they have done in Kerala. The hon. Law Minister

[Shri Ranga]

here must have had a hand in it in those days. The Congress was defeated. It was not at all able to form a ministry. Then they had the PSP to form a Ministry. They said they were not hankering after power, they would remain behind and they would help the minority P.S.P. ministry to remain in power. Could they ever be patient without power? Within a few months PSP Chief Minister friend was transformed into gubernatorial clothes and robes. They themselves stepped into power first as partners with P.S.P. and then as sole proprietors of power. Would not the same fate come upon my hon. friend, Dr. P. C. Ghosh tomorrow or the day after? Could we be sure that these people would ever be able to abstain from power, from their thirst for power? For twenty years they have enjoyed it and like a man-eating tiger they can never be happy until they go on killing one after another these democratic decent personalities in these various non-Congress areas and non-Congress governments. That is the reason why we are not able to appreciate the moves that the Government makes.

Yet they are suffering from a paralysis, a paralysis of not being able to do the right thing at the right moment, of not being able to be content with doing only the right thing and not also the wrong thing. What is worse is this. It used to be said of some kind of an artisan that if he cannot deceive anyone else he would deceive his wife and if he cannot deceive even his wife he would deceive himself. That is the nature of these people. If they cannot deceive anyone else they will be deceiving themselves. That is what they are doing with their own groups, the majority groups and the minority groups. With all these confabulations they are trying to keep under their power even their own presidents not only at the top but at the State levels also.

Sir, that is the kind of Government we have to deal with. That is why it is impossible for us to show any kind of patience with this Government. What is it that I want in their place? True, we are not able to make a majority. True also we do not want any of these defections from these honourable gentlemen. We know the nature of these defectors from the Congress. They have displayed themselves to the whole country, and the world is laughing in its sleeves at the manner in which these Congressmen behaved when they became defectors of their own rank and file. Are you sure there are not prospective defectors among these Congress M.Ps. here? Are you sure that even within their own Cabinet there are not people who are searching their hearts when it would be possible, when it would be convenient for them to flirt with us first then whisper to us and after that come over to us if only we are unwise enough to embrace them. Sir, we are not going to embrace them. We do not want any embraces from these people. Let those people within the Congress who have got the moral courage to leave that organisation, wait until the next general elections come, or let them demand, after leaving the Congress, mid-term elections and let them stand as independent people, even if they do not have the political foresight to come and join either us, or the Jan Sangh or the Socialist Party or even the Communist Party. We know there are some people in the Congress who want to join the Communist Party. Let them join that party. Let them first come and seek the franchise of the people and, thereafter, let them come and join us as honourable men.

Why do I say this? Because of the manner in which the so-called defectors in Haryana and Bengal are behaving today and their friends in the Kranti Dal are likely to behave in the other areas. Who are the Kranti Dal people? From what Shri Humayun Kabir has written today in the *Hindustan Times*, one can easily see that they are only too anxious, too impatient to play the same role the erstwhile P.S.P. gentleman has played.

It is on board that this government and the Congress Party have undermined our political morality and political decencies and lowered the standards of behaviour of our public workers and that is why we condemn this government and condemn this party and we warn the country not to continue to place its confidence in these gentlemen and their chief.

SHRI VIKRAM CHAND MAHAJAN (Chamba): Mr. Chairman, Sir, the present motion under discussion is most inappropriate and uncalled for in the present circumstances, because the administration in the States from which the Ministries have been dismissed have completely failed. So

far as Haryana is concerned, we have the report of the Governor, which is the evidence before the House, that the entire administration had completely failed and the junior officers, because of the fear of transfer, were doing things which under normal circumstances they could not be expected to do in any State. Similarly, in Bengal the administration had completely failed, there was complete lawlessness and it was very difficult for an ordinary citizen to carry on his normal activities.

The learned friends from the opposition have said quite often that they want democracy and rule of law and rule by the majority. But when it comes to a United Front Ministry and it happens to be a minority government, then they change their tone and say "no, the minority government must continue because the Chief Minister wants it". And what does that Chief Minister say? He says "I represent the minority government and I shall call the Assembly when it is convenient to me".

If they want to uphold democracy, the rule of law and rule by majority, they must not fight shy of having a vote of confidence in the Assembly. The very fact that they declined to call the Assembly, the very fact that the United Front Government failed to call the Assembly in Bengal and wanted to continue as a minority government shows that they were not interested in upholding democracy and, therefore, it was the bounden duty of the Governor to dismiss that ministry.

The great leader of the Swatantra Party has said that Congress is trying to attract defection and is trying to support the defectors. But when they support the defectors from the Congress who form the United Front Ministries, perhaps they think that they are doing a great act of service to the country. But when the Congress Party supports defection, it becomes a sin. Because the Congress is supporting the defectors it is a sin, but when they support the defectors it becomes an act of goodness, an act of greatness and an act of service to the country.

There cannot be two rods for the same thing. If defection is bad, it is bad in U.P. also, it is bad in Madhya Pradesh also, it is bad in Bihar also. But if there is defection in Bengal, it becomes bad and if it is in U.P. it becomes good. They are trying to measure the same act with two different rods. Therefore my submission is that the speech of Shri Ranga, so far as it relates to defections, is most inappropriate.

Then, they are trying to say that the foreign policy of this country supports imperialism and colonialism. My submission is that the foreign policy of our Government has always been against imperialism and colonialism. The Indian representatives in the United Nations have always supported the cause of the downtrodden people of South Africa and Rhodesia. It is a perversion of facts to say that the Government of India is supporting the imperialist powers. The fact is that more often than not India has moved resolutions to support the governments of the people of South Africa and Rhodesia. Even now a resolution has been moved supporting the cause of those people.

Another speaker said that the foreign policy of India is a policy of convenience. If the policy of peaceful co-existence, of increasing foreign trade, of improving the economic conditions of the country is a policy of convenience, then, of course, the foreign policy can be charged that it is a policy of convenience; but if it is in the interest of the country to increase this trade, to increase the number of friendly countries, to have better relations and peaceful living with the rest of the countries, then my submission is that there could not be a better policy than the present foreign policy of our country.

Then, another allegation has been made that commerce and trade are used for the benefit of a particular group of individuals and exorbitant profits are made. An instance is cited of the sugar policy. My submission is that the present sugar policy of our country is the correct policy in the present circumstances. I will give two reasons for it. Now sugar is controlled in our country and the result is that sugarcane is also controlled. The farmer who grows sugarcane finds that other cash crops bring better results than sugarcane; therefore, he diverts his land to the growing of crops which give a better return. The result is that less acreage goes to sugarcane and more to other crops.

Now the country was facing a sugar crisis. Therefore the Government of India

[Shri Vikram Chand Mahajan]

thought that some incentive must be given to the sugarcane growers and the sugar industry so that more sugarcane is produced. Consequently the price of sugarcane was raised but even then it was found that the farmer was diverting the sugarcane to the gur industry which was not controlled and where the prices were not controlled. Consequently the Government had to give incentive to the sugar factories to see that they compete with the gur market. So, sugar had to be decontrolled. But Government wanted to see that the poorer sections of the people do not suffer; therefore they said that a particular quantity will have to be sold to them at controlled prices so that the lower income groups also have the benefit of lower sugar prices. Therefore partially it was decontrolled and partially it was kept controlled. My submission is that this is a wrong allegation to say that the decontrol was done for the benefit of a few profiteers or to please a certain section of the people. Such like allegations can easily be made. But if a little thought is given to the basic reasons why a particular policy is followed, that would be a more responsible way of putting things.

Finally, my submission is that there are some people who always happen to meet a particular fate. It is a tragic role that they normally play in history. I may give an instance of the Chief Minister of Haryana. He has always had a tragic end of his career. He was once a Minister in Pratap Singh Kairon's Ministry in Punjab in 1962 and he would not resign and, ultimately, he was dismissed. Again, he was going through the same crisis and he would not resign. But, as a consequence, he met the same fate. It is the destiny which one has to face; one has to pay for one's own doings.

With these words, I submit that the No-Confidence Motion should be rejected by the House *in toto*.

श्री जगन्नाथ राव जोशी (भोपाल) सभापति महोदय, अविश्वास के प्रस्ताव का पूरी ताकत के साथ समर्थन करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं। यह अच्छा होता कि सामने जो बैठनेवाले हैं वह सुनने के लिये ज़रा यहां रहते। या तो वह यह समझ कर चले गये होंगे कि आगे जाना ही है बाहर तो उस के पहले ही खुद चले जायें। यह ठीक नहीं है। जिस प्रजातंत्र की बात को ले कर यहां कल गृह मंत्री जी बहुत बोले तो उन के सामने हम भी कुछ बोलना चाहते थे। यह प्रजातंत्र नहीं है। जब कि अविश्वास का प्रस्ताव सदन के सामने पेश है, न प्रधान मंत्री हैं, न उप प्रधान मंत्री हैं, न वित्त मंत्री हैं, न गृह मंत्री हैं, न राज्य स्तर के गृह मंत्री हैं। यह क्या है? यह जो दृश्य दिखाई दे रहा है..... (**व्यवधान**) .....यानी विरोधी दलवाले क्या कहना चाहते हैं इस को वह सुनना नहीं चाहते। यह कोई अविश्वास का प्रस्ताव एक बंगाल की बात को लेकर नहीं आया। पूरी सरकार पर, सरकार की जितनी कार्यवाही है, चौथे आम चुनाव के बाद जितनी बातें हुई हैं उन सब बातों को लेकर यह अविश्वास का प्रस्ताव आया है। इस लिये यह अच्छा होता कि प्रमुख जो हैं इस के वह यहां सुनने के लिये रहते। मैं याद दिलाना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, कि सब से पहले अविश्वास का प्रस्ताव 1963 में पहली बार आया। इस देश का पूरा विश्वास कांग्रेस के साथ था, 1963 तक बना रहा और पहली बार अविश्वास का प्रस्ताव इस सदन में जब पेश किया गया उस को स्वीकार किया गया, तभी यदि होश में आते, संभल लेते, समझने की कोशिश करते कि अविश्वास का प्रस्ताव क्यों आया, क्यों यह स्वीकृत हुआ तो 67 के चुनाव में जो स्थिति आई वह न आती। 1967 के चुनाव में जनता ने बता दिया कि हमारा विश्वास नहीं है, न इन के राम-राज्य पर है न इन के कामराज पर है। किसी पर भी भरोसा नहीं है। यह जनता ने बता दिया। अब वास्तव में तकाजा यह था प्रजातंत्र का कि इस अधिकार का इतने दिन तक उपभोग करने के बाद वह यह समझ लेते कि प्रजातंत्र में कभी यह दल अधिकार में रहेगा, कभी दूसरा दल अधिकार में रहेगा वह भी कैसा काम करते हैं, इस का मौका देते। इस देश के अन्दर सब प्रयोग हो चुके हैं। यहां विश्वामित्र का पतन भी होता है, फिर विश्वामित्र मेनका

उर्वशी सब का त्याग कर के सब के सामने एक आदर्श के रूप में आ खड़े होते हैं। मैं जब गोवा जेल में था तो मेरे साथ एक कवि थे। उन्होंने कहा कि आज का शासन जो है वह आधुनिक विश्वामित्र है। मेनका आये, इसी लिये तपस्या के लिये बैठता है। गलती क्या हुई? मोह में हम न फंसते, इस बात को हम समझ लेते तो यह नौबत न आती। अभी-अभी खबर आई है कि पंजाब में दल-बदल हुआ, पंजाब के मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दे दिया।

16 Hrs.

अब फल ही हरियाणें पर यह सब बात आई अर्थात् मंत्रिमंडल भंग करके राष्ट्रपति का शासन लागू किया गया। वैसे मेरे नजदीक एक बुढ़िया मर गयी इस का अफसोस नहीं लेकिन अफसोस तो इस बात का होता है कि मृत्यु दरवाजा देख लेती है। एक बार पता चले कि अगर दिल्ली में बैठी हुई सरकार मदद करने जा रही है तो यह बदला हुआ है। हमारे माननीय गृह मंत्री चाहें या न चाहें दलबदल अच्छा या बुरा किन्तु उस का असर तो जरूर होता है यह आज ही पता चला। हरियाणे का असर पंजाब पर जरूर होगा किन्तु यह दलबदल भी क्यों होता है इस का थोड़ा अनुसंधान करके हम समझ लें तो सारे देश के लिए अच्छा होगा। यह कोई आज की बात नहीं है। बदल कोई बुरा नहीं होता। Change is the law of life. बदल हमेशा रहता है। If there is anything permanent in this world, that is nothing but change. इसलिए हमारे पिछले ऋषि, मुनियों ने अपनी अन्तप्रेरणा को प्रकट किया :

"असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय
अमृत्योर्मा अमृतं गमय।"

यानी हम को बदलना है हम को जाना है, किन्तु बुराई से अच्छाई की ओर जाना है। बदल हो तो अच्छाई में बदल हो यह हम समझ सकते हैं। इसलिए कोई एक आदर्श निर्माण करना पड़ता है किन्तु मुझे आप क्षमा करें यह कहने के लिए कि अपने देश को आजादी मिले In our anxiety to get Independence to this country हमने आदर्श और तत्व को पैरों तले रौंदना शुरू किया। हमारे दिलों के अन्दर भी पिछले बीस साल में अधिकारों का मोह घुस गया और यह जो आज दलबदल है यह इसके पहले भी बदल होता था। There were group defection, loyalties were changed from one group to another.

16.03 Hrs.

[Mr. Deputy-Speaker *in the Chair*].

इसके कारण एक पार्टी होने के बाद भी मंत्रिमंडल बदला करता था। मैसूर में हम ने देखा कि हालांकि दल एक ही था लेकिन पहले श्री के० सी० रेड्डी मुख्य मंत्री बने, श्री हनुमन्तय्या बने और श्री निजिलिंगप्पा बाद में वहां के मुख्य मंत्री बने। हर एक नये मुख्य मंत्री के साथ नीतियां भी बदलती थीं। जिस मैसूर प्रदेश से मैं आता हूं वहां अब श्री निजिलिंगप्पा का मंत्रिमंडल बना हुआ है और इसलिए पहले के मुख्य मंत्री के काल में चलने वाली नीतियों में भी तबदीली आई है। एक मंत्रिमंडल ने इंटैग्रेटैड मैडिकल कोर्स मैडिकल कालिज में स्टार्ट किया, दूसरा मंत्रिमंडल आया तो उन्होंने उसे बन्द कर दिया। श्री हनुमन्तय्या जब वहां पर चीफ मिनिस्टर की हैसियत से बैठते थे तो उन्होंने वहां की विधान सौध में एक बढ़िया शब्द लिखवाया था : God's work is Government's work. लेकिन उनके बाद जब वहां पर दूसरे मुख्य मंत्री आये तो उन्होंने उसे हटवा दिया as though Government's work is Satan's work. इसलिए जैसा मैंने कहा एक दल के अन्तर्गत भी यह बदलाव होता था और उसमें भी नीतियां बदलती रहती थीं। जब श्री हनुमन्तय्या मुख्य मंत्री रहे तो उन्होंने शिक्षा नीति में परिवर्तन कर के जनवरी टु जनवरी रखा। जब श्री हनुमन्तय्या नहीं रहे तो दूसरे मुख्य मंत्री ने मार्च टु मार्च किया। यहां पर एक ही दल होने के बाद भी यह डिफैक्शंस चलते थे, इंट्रीग्स चलती थीं, ग्रुप

[श्री जगन्नाथराव जोशी]

डिफैक्शंस चलते थे और मिनिस्टरियां बदलती थीं। केरल में कई कांग्रेस की मिनिस्टरियां खत्म हुई। बिहार में यही हाल हो गया। मध्य-प्रदेश में भी वही हाल हुआ। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि उसको रोकने के बजाय प्रोत्साहन दिया जाने लगा।

मध्य प्रदेश के श्री द्वारका प्रसाद मिश्र जब सन् 1951 में बाहर आये तो उन्होंने सार्वजनिक रूप से पंडित जवाहरलाल की जिस तरह नुक्ताचीनी की और उन्हें भला बुरा कहा और जैसी भाषा का प्रयोग उन्होंने इस चीज के लिए किया था वह प्रजातंत्र को शोभा नहीं देता। हम ने कहा था कि हमारा उनसे विरोध जरूर है लेकिन इस का मतलब यह नहीं है कि हम गालीगलौज करके विरोध को प्रकट करें। कितने ऐसे ही आदमी कांग्रेस में आ जाते हैं, पी० एस० पी० में आ जाते हैं और फिर उससे बाहर चले जाते हैं। वाइस चान्सलर बनते हैं और फिर कांग्रेस के अन्दर आ जाते हैं। वह कांग्रेस के अन्दर जायें मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं, एक दल छोड़ कर दूसरे में चले जाते हैं लेकिन होता यह है कि दल छोड़ कर कांग्रेस में शामिल होने के लिए उनको प्रमुख पद दिया जाता है और वह मुख्य मंत्री बनते हैं कोई इस में बिलकुल लज्जा ही नहीं मालूम होती है।

विद्आउट ऐनी स्क्रुपल्स हमारे जनसंघ के अध्यक्ष श्री मोलिचन्द्र शर्मा को इसी तरह उधर से फोड़ लिया गया। अभी हमारे गृह मंत्री कल हरियाणे के ऊपर हो रही बहस के समय यह दो व्यक्तियों द्वारा सुबह, शाम पार्टियों की अदल बदल के बारे में चिन्ता प्रकट कर रहे थे और कह रहे थे कि इसे सबों को मिल कर रोकना चाहिए और यह कह र थे कि एक व्यक्ति जिस पार्टी के टिकट पर किसी असेम्बली आदि के लिए चुना जाय वह अगर वहां पहुंच कर पार्टी बदल ले तो जनता को उसका पूर्ण बहिष्कार करना चाहिए और उस शख्स को आयन्दा वोट नहीं देना चाहिए। लेकिन हमारे ही भूतपूर्व अध्यक्ष श्री मौलिचन्द्र शर्मा को इन लोगों ने गुड़गांव क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस टिकट दिया है। आखिर जिनके हाथ में अधिकार है, शासन चलाने की बागडोर है उन पर इसकी ज्यादा जिम्मेदारी होती है। इस जिम्मेदारी के साथ यदि हम ठीक चलते और अपने ही अन्दर यह जो अधिकारों के बारे में व्यामोह पैदा हो गया है उसको निकाल कर यह लोग विरोधी दलों के नेताओं के साथ मिल कर बैठते और देश का भविष्य ठीक बनाने हेतु यदि हम सब मिल कर प्रयत्न करते तो यह नौबत न आती। 63 के दिनों में क्यों आई ? इसी तरह 67 के बाद भी राजस्थान के अन्दर अपने ही हाथ में अधिकार रखने की कोशिश की गई। हम उन को भी खुली छूट देते, मौका देते उनको भी करने देते, अधिकार चलाने देते। अब विरोधी दलों को केवल यह आदत लग गयी थी कि आलोचना करो, आलोचना करो, टीका टिप्पणी करो जिम्मेदारी भी किसी को निभानी पड़ती तो उनको पता चलता। कांग्रेसी शासन जहां-जहां बना उन पर एक बड़ी भारी जिम्मेदारी थी। 20 साल के पिछले कांग्रेसी शासन से लोगों ने बड़ी आशाएं बांधी थीं। लोग उस की ओर बड़ी उम्मीद से आंखें लगा कर देखते थे लेकिन मुझे बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि लोगों को निराशा ही पल्ले पड़ी। जहां कम्युनिस्ट पार्टी अधिकार को अपने हाथ में लेकर बैठी वहीं उन्होंने ऐसा ढंग अपनाया, ऐसा रवैय्या अपनाया कि न केवल कांग्रेसी शासन को ही चोट लगी बल्कि सारी जनता की जो भावना थी उस पर भी उन्होंने पानी फेर दिया। आपका विश्वास प्रजातंत्र में हो या न हो वह बात अलग है किन्तु एक बार when you decide to work within the framework of a given constitution and with the idea of a democratic tendency here, उसके खिलाफ कुछ करें तो यह बात ठीक नहीं है। नक्सलबाड़ी के अन्दर अगर कोई एग्रेरियन प्राबलम होती

Naxalbari is no agrarian problem. It was within the purview of the provincial Government to enact suitable legislation and to give proper relief to the peasantry. वह करने के बजाय यदि कोई वहां विद्रोह का झंडा खड़ा करने की चेष्टा करे, इतना ही नहीं When the Naxalbari situation gets a patting from the Radio Peking, all the more it sounds sinister. कोई विदेश की ताकत इस देश के अन्दर दखल दे और यहां भी जब तब गड़बड़ियां होती रहें उन्हीं बातों को लेकर हमारे बीच के अन्दर कोई एक दीवार, खाई खड़ी कर दें तो इसे कोई सच्चा राष्ट्रभक्त बर्दाश्त नहीं कर सकता । कम्युनिस्ट भी राष्ट्रभक्त होने चाहिए । कम्युनिज्म कोई एक आर्थिक नीति हो सकती है । इसका मतलब यह नहीं है कि मैं किसी का पिछलग्गू बनूं । इसका मतलब यह नहीं है कि 1962 के दिनों में बड़े पैमाने पर जब हमारे देश पर बाहरी शत्रु ने हमला किया और देश की आजादी खतरे में पड़ी थी तो यह कम्युनिस्ट बंधु चीन के माओत्सेतुंग के चित्र को हाथ में लेकर कालीकट और कलकत्ते में घूमें और ऐसा किया जाना एक लज्जा की बात है । इसको हम कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते, बिलकुल बर्दाश्त नहीं कर सकते । कोई एक जिम्मेदार नेता आकर कहे कि The High Court Judge should be gheraoved. That is the last word of wisdom औद्योगिक अशान्तता को दूर करना है । If you want to arrest the industrial unrest in this country, gherao is not the solution. हमें उसके मूल में जाना होगा और जब तक हम मूल में नहीं जायेंगे औद्योगिक अशान्तता दूर नहीं होने वाली है । इस प्रजातंत्र पर ही जिनका भरोसा नहीं है ऐसी स्थिति सब के सामने लाकर उन्होंने सब की स्थिति खराब कर दी है । इसलिए हम यह समझते हैं कि हरियाणा के अन्दर जैसे उन्होंने वहां की शांति, व्यवस्था बिगड़ गयी थी इसी बात को लेकर **अंडर आर्टिकिल 356** यदि वह डिसमिस कर देते तो बहुत अच्छा होता किन्तु पिछले इन 20 सालों के अन्दर में बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि इस देश के अन्दर कम्युनिस्टों को किसी ने अगर बढ़ावा दिया होगा तो वह कांग्रेस ने दिया है । The relation is just between the disease and the dirt. Under the dirt of the Congress alone the disease of Communism grows. केरल को जैसे उन्होंने अपने हाथ से जाने दिया वैसे कहीं आगे न हो । हम चाहते हैं कि हमारे देश के जितने भी सीमावर्ती क्षेत्र हैं वह सुरक्षित रहें । और देश की सुरक्षा सब से बड़ी चीज है और उसके सामने कोई दलगत भावना नहीं आ सकती और न आनी ही चाहिए । जहां देश की सुरक्षा का सवाल आ जाता है सब कंधा से कंधा मिला कर खड़े रहें । इसलिए सन् 1962 के दिनों में जब चीन का संकट देश के सामने आकर खड़ा हुआ तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जब देशों के सामने यह बात रखी :

"उत्तरम् यत समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम् वर्षम तद्भारत्म ताम" । कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक समग्र भारत एक है । विष्णु पुराण में यह समग्र भारत का वर्णन आया है जो कि मैंने अभी बतलाया है और आज भी आपको उसके पढ़ने से समग्र भारत का यह वर्णन मिलेगा और आगे आने वाली पीढ़ी इस समग्र भारत की बात को भूल न जाय इसलिए उन्होंने इसे बतला दिया है । Right from the deepest seas of the South to the highest peaks of the Himalayas the whole country is one and indivisible.

समग्र भारतवर्ष बिल्कुल एक हैं और इस नाते भारत का हर एक आदमी कन्धा से कन्धा मिला कर चीन के खिलाफ खड़ा हुआ । किन्तु दुःख यही है कि सन् 62 में अपनी गफलत के

[श्री जगन्नाथ राव जोशी]

कारण हम ने ठोकर खाई लेकिन उस ठोकर को खाने के बाद भी हमें होश नहीं आया। चीन इन दिनों में जो आया वह बिल्कुल कन्वेंशनल आर्म्स लेकर आया वह ऐटम बम लेकर नहीं आया था लेकिन हम को समझाया गया कि **वेव्स आफ्टर वेव्स** ऐसी चीनी सेना हमारे ऊपर चढ़ कर आई लेकिन मेरा कहना है कि भारत में भी आबादी कुछ कम नहीं हैं। हमारे डा० चन्द्रशेखर से पूछिये तो कहेंगे कि बहुत है। यदि चीन **वेव आफ्टर वेव** भेज सकता है तो भारत **सुपर वेव आफ्टर सुपर वेव** भेज सकता था और हम उसे पीछे हटा सकते थे but we do not know how to make an intelligent use of our own population. डिफेंस में हम ने उसका उपयोग नहीं किया, उद्योग में उसका उपयोग नहीं किया। कराग्रे-वसते लक्ष्मी। घोड़े पर पैसा लगा कर लक्ष्मी पैदा नहीं होती, पसीने से पैदा होती है, परिश्रम से पैदा होती है। इसीलिये कहा गया कराग्रे वसते लक्ष्मी। यह नहीं कहा कि धनी आदमी के यहां लक्ष्मी होती है। परिश्रम कर के और पसीने से लक्ष्मी प्राप्त की जा सकती है: लेकिन हाथ का काम देने की दृष्टि से कोई योजना नहीं बनी। इस लिये सरकार के बारे में अगर कोई प्रस्ताव आ सकता है तो केवल अविश्वास प्रस्ताव ही आ सकता है, क्योंकि जिनको खुद पर भरोसा नहीं है उन पर दुनिया भरोसा नहीं कर सकती। हम कोई नीति निर्धारित करते हैं तो हमको लगता है कि रूस क्या कहेगा, अमेरिका क्या कहेगा यह क्या कहेगा, वह क्या कहेगा। हम योजना बनाते हैं तो सोचते हैं कि पैसा कहां से आयेगा, यह देगा या वह देगा। मैं कहना चाहता हूं कि जिनको खुद पर विश्वास नहीं है, खुद के बलबूते पर कुछ कर सकने का विश्वास नहीं है, दुनिया उन पर भरोसा नहीं करती। इसलिये 1962 के बाद यदि हम नीतियों के अन्तर्गत परिवर्तन कर लेते तो देश की सुरक्षा की दृष्टि से हम कई कदम आगे जाते। किन्तु फिर-फिर ठोकर खाना यही मानव स्वभाव बना है। इस शासन की भी ऐसी नीति देख कर दुःख होता है और मुझे कहना पड़ता है I am constrained to say that even genius has got limitation but stupidity is boundless. बार बार वह ठोकर खायेंगे और बार-बार वही गलती करेंगे। इससे कोई फायदा नहीं होता।

मुझे एक बात और कहनी है। मैं गोआ जेल में रहा। डेढ़ साल जेल में रहा। मेरे एक साथी आज भी पुर्तगाल के जेल में हैं, मोहन रानाडे, तेलु नास्कारमिस। उनको 26 साल की सजा हुई थी। 20वीं शताब्दी में हम रहते हैं। हम को पता है कि अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में क्या होता है। अपने ही पड़ोसी पाकिस्तान का रवैया अपने बारे में क्या है हम को पता है। कोई ऐसी बात नहीं थी। लेकिन 1947 से लेकर 1961 तक का इतना अनुभव होने के बाद जब तक वह हमारे लोगों को हमारे हाथ में नहीं देते तब तक उनके लोगों को हम ने क्यों छोड़ा? आज हम जब प्रधान मन्त्री को पत्र लिखते हैं, राष्ट्रपति जी को पत्र लिखते हैं, विदेश मंत्री जी को पत्र लिखते हैं, तो जवाब आता है कि कोशिश कर रहे हैं। पूछने पर पता लगता है कि क्या कर रहे हैं। हमारे डिप्लोमेटिक सम्बन्ध भी नहीं हैं, हमारे लिये करेगा कौन? वह बेचारे बैठे हैं 26 साल की सजा भोगते हुए, जिसमें से दस साल हो गये हैं। जब कि दुनिया में हम बड़े गर्व के साथ कहते हैं कि कि 50 करोड़ ब्रदरहुड का भारत अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में यह करता है वह करता है, लेकिन जो अपने स्वातन्त्र्य के लिये लड़ा, मामूली आदमी की तरह लड़ा, सामान्य सिपाही की तरह लड़ा, यदि हम उस को रिहा करा कर नहीं ला सकते वापस, तो क्यों हम दुनिया की बात करें? अपने हाथ में जो था उसको भी हम ने छोड़ दिया। किन्तु इससे भी हम ने सबक नहीं सीखा। फिर 1965 में ताशकन्द टेबल में बैठ कर रूस को मध्यस्थ बना कर हम पाकिस्तान के साथ वार्ता करते, तो आज की हमारी स्थिति क्या आती? आज हमारा

कागों पाकिस्तान के हाथ में है, वह नहीं देता। हम ने दे दिया। क्यों दे दिया ? यानी एक बार यूनिलैट्रली इंटरनेशनल गुड फेथ दिखाने के बाद भी यह देखने के बाद कि इट **हैज नाट रिस्पांडेड**, पुर्तगाल के बारे में पता लगने के बाद भी पाकिस्तान के रवैये का पता लगने के बाद भी जब सरकार फिर-फिर गलती करती है तभी तो मैंने कहा कि **स्टुपिडिटी इज बाउंडलेस्**। आदमी एक बार ठोकर खाता है, होश में आता है, सम्भल लेता है, नीति में परिवर्तन करते हुए नीति निर्धारित करता है, सब को विश्वास में लेता है और आगे जाता है : आज वह मेरा साथी जेल में रहे। मुझे बड़ी शर्म आती है जब यह पता चलता है कि हम तो यहां आकर बैठ गये, लोक सभा में आकर बैठ गये और वह जेल में बैठा हुआ है। जिस गोआ की आजादी को लेकर हम लड़े, गोलियां झेलने के लिये गये, जेल में रहे, आज यदि उसी जगह के आदमी को हम रिहा नहीं करा सकते तो हमारी वैदेशिक नीति सफल है ऐसा कहने का क्या लाभ है ?

"Example is better than precept"

दुनिया में हमारा कोई मित्र नहीं रहा, दुनिया में कोई हमारी सहायता करने वाला नहीं रहा, दुनिया में हमारी बात को मानने वाला नहीं रहा, फिर भी हम कहते घूमें कि हमारी वैदेशिक नीति सफल हुई है तो हम वैदेशिक नीति सफल होने का कोई नमूना पेश नहीं करते।

देश की सुरक्षा की दृष्टि से मेरा नम्र निवेदन है, क्योंकि वित्त मंत्री जी यहां आये हुए हैं, कि चीन का हमला होने के पहले सुरक्षा के नाम पर हम लगभग 250 करोड़ रुपये खर्च कर रहे थे जबकि आज हमें 950 करोड़ रु० खर्च करने पड़ रहे हैं। Every political aspect has got an economic bearing. इसको हम भूल नहीं सकते। हमारी मामूली सी गलतियां क्यों न हों किन्तु एक बार हम चीन को तिब्बत की सीमा के इस ओर ले आये और वह हमारे घर में आकर बैठ गया। कल कोई कह रहा था कि 21 नवम्बर का ऐसा दिन था वैसा दिन था। तब मेरे दिमाग में आया कि This is the day when China decided to cease fire unilaterally 21 नवम्बर के दिन चीन पीछे गया किन्तु हमने क्या किया ? हम ने उस समय बड़े जोर से बातें कही थीं। Until the last soldier is driven out जब तक चाइना पीछे नहीं हटता तब तक हम चुप नहीं रहेंगे। किन्तु वह बात वैसे ही टल गई।

हर 20 अक्तूबर को हम राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं, किन्तु एकता क्या चीज होती है, इस पर गौर नहीं करते, इस पर गम्भीरता से विचार नहीं करते कि एक ही चीज एकता का चिन्ह मानी जाती है कि हम देश की सुरक्षा को ध्यान में रख कर काम करें। देश के अन्तर्गत जो जनता है, उस जनता की जो एकता है उसके आधार पर हम बाह्य आक्रमणों और अन्दर की गड़बड़ियों का मुकाबला नहीं कर सकते। देश को एक करने के लिये बहुत सी बातें होती हैं, बहुत सी बातों से नेशनल इंटेग्रेशन होता है। But do we know what are the forces and factors that integrate the people of this country ?

यह एक ही भूमि है। इसीलिये कहते हैं कि :

विष्णुपत्नि नमस्तुभ्यं पादस्पर्शं क्षमस्वमे

यह विष्णु की पत्नी है। हमारे लिये माता है। सब की माता है चाहे हम काश्मीर में रहते हों चाहे कन्याकुमारी के अन्तर्गत हों। यह भमि है जो हम को जोड़ती है, संस्कृति है जो हम को जोड़ती है। वह **बे आफ लाइफ** है ! हमारा जो जीवन दर्शन है वह कहीं क्यों न हो वह एक जैसा है। लेकिन बीस साल के अन्दर इस सरकार ने हर क्षेत्र में दुर्भाग्यपूर्ण अलगाव की प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया। पुर्तगीज के गोआ से हटते ही जब गोआ आजाद हुआ तो हमने उसको अलग रक्खा। जब 1956 रिआर्गेनाइजेशन के बाद दिल्ली की स्टेट खत्म हो गई, कुर्ग की अलग स्टेट खत्म हो गई, अजमेर खत्म हो गया, इकाइयां बड़ी बना दी, तब पुदुचेरी अलग क्यों हो ?

[श्री जगन्नाथ राव जोशी]

What is the basis for Pondicherry to exist today ? साथ ही 2,000 लोगों का गांव माहे पश्चिमी तट पर केरल में है, पुदुचेरी पूर्वी तट पर है। न भाषा की समानता है न प्रादेशिक संलग्नता है, न तो कंटिगुइटी है और न कुछ और है, लेकिन छोटी-छोटी एकाइयां बनती जा रही हैं और वह भी नागालैंड जैसी। प्रदेश भी बनाया तो नागप्रदेश, नागभूमि या नागनाड बनाना था, नागालैंड क्यों ? यह अंग्रेजी का प्रयोग कहां से आया, क्यों किया ? पता नहीं चलता कि इसके पीछे कौन सी बात काम कर रही है, कौन सा भाव काम कर रहा है। और उस छोटे से राज्य के बनने के बाद भी There is another demand for a different Federal Government of Nagaland ? और उन विद्रोही नेताओं के साथ तीन साल हो गये वार्ता चल रही है लेकिन अभी तक वह सफल नहीं हुई है। होगी भी कैसे ? Because they are underground, our leaders are above ground and there is no common ground between them.

आज तक कामन ग्राउंड मिल ही नहीं रही है। तीन साल से वार्ता चलने के बाद भी मुझे लगता है जैसा कि फिलासफी अथवा तत्व-ज्ञान के बारे में कहा गया है कि What is philosophy ? It is nothing but a search by a blind man in a dark room for a black cat which is not there. वैसे ही यह होती है। तीन-तीन साल हो गये लेकिन हम क्या करना चाहते हैं, क्या करने जा रहे हैं, कुछ पता ही नहीं है। तीन-तीन साल तक इस तरह की वार्ता कर के दुनिया के सामने हम गलत ढंग पेश करते हैं कि there is such a thing as a Naga problem. वास्तव में हजारों मील दूर से आने वाला अंग्रेज हम को एक बनाता है और हम जो हजार-हजार साल से इस देश में रहते आये हैं, इस मां के पुत्र बन कर रहते आये हैं, वह इसको एक नहीं बनाते, गले नहीं लगाते। अखिल विद्यार्थी परिषद् की ओर से एक कार्यक्रम किया गया था और उपुसी क्षेत्र के विद्यार्थियों को बम्बई के पूना क्षेत्र में ला कर इंटर-स्टेट लिविंग का नमूना पेश किया, जिससे पता चलता है कि हम आज एक क्यों हैं। आज यहां पर इधर-उधर की ऐक्टिविटी की बात कहते हैं, लेकिन Do we have any positive thinking कि हम सारे एक हैं ? आज हमारे अन्दर जो एक अलगाव की प्रवृत्ति काम कर रही है उसके लिये I do not blame the people जनता को सही दिशा दो, जनता के सामने सही विज्ञान रक्खो, वैसी कोई चीज यह नहीं रखते। समय की मांग थी इसके कारण ही पूरे देश के अन्दर एकता की बात को लेकर सारी जनता खड़ी है, यह जो सुन्दर दृश्य दिखना चाहिये था, वह दिख नहीं रहा है। क्या कारण है ? 1947 में आप माने या न मानें, मां का जो एक चित्र था वह टूट गया। मैं भौगोलिक चित्र की चिन्ता नहीं करता हूं क्योंकि भौगोलिक एकता तो बनाई जा सकती है और वह बदलती भी रहती है किन्तु अपने मन में जो चित्र था वह अभंग है क्या, एक है क्या ? हम इसको मानते हैं कि चाहे भाषायें कई हों, जातियां कई हों, रीति-रिवाज कई हों, रहन-सहन, खान-पान कई हों लेकिन फिर भी सारा भारत एक है, मरेंगे तो साथ, जियेंगे तो साथ। यह भावना हमारी होनी चाहिये।

मुझे कभी-कभी समझ में नहीं आता है कि समाजवाद बोलने वाले, साम्यवाद बोलने वाले किस तरह इस बात को लेकर चलते हैं। कि प्रान्तबन्दी रहे ताकि एक प्रान्त में चावल सस्ता मिले और दूसरे प्रान्त में चावल के लिए लोग तरसें। मैंने पूना में देखा। लोग खड़े हुए थे, लम्बी लाइन उनकी लगी हुई थी। मैंने पूछा, क्यों खड़े हो भाई। बोले चावल मिलता है। मैंने पूछा कितना मिलता है, बोले सौ ग्राम मिलता है। सौ ग्राम चावल के लिए इतनी बड़ी लाइन। मैंने कहा गांधी जी का जो एक सपना था ग्राम राज का वह पूरा हो गया बिना ग्राम के हम चलते ही नहीं हैं, सौ ग्राम चावल, ढाई सौ ग्राम चीनी, पांच सौ ग्राम गेहूं, आलू भी साढ़े सात सौ ग्राम। जीवन किलो तक पहुंचा ही नहीं। ग्राम में ही हैं पूरे बीस साल से। क्या अपने ग्राम को

आत्मनिर्भर बनाया है, क्या सारे समाज को आत्म निर्भर बनाया है और क्या गांधी जी के सपने को साकार करने की कोशिश की है। देश में आज भी उपजाऊ भूमि है। भारत का नाम स्वर्ण भूमि था। दुनिया भर इसको लूटने के लिए पहुंची। बारह सौ साल का इतिहास इसका साक्षी है। इसको लूटने वाले बहुत आए। लेकिन आज भी हमारी भूमि सोना उगलने वाली भूमि है। किन्तु जो नई-नई नीति चलाई जाती है, प्रतिबन्ध खड़े किये जाते हैं उनके कारण पता ही नहीं चलता है कि कहां कितना पैदा हुआ। फूड कारपोरेशन के पुराने चेयरमैन श्री टी० ए० पाई ने साफ कह दिया था कि सरकार के पास कोई सही आंकड़े नहीं हैं उत्पादन के सम्बन्ध में। इसका कारण यह है कि प्रान्त बंदियों के कारण पता ही नहीं चलता है कि कितना गेहूं पंजाब में पैदा हुआ है, कितना हरियाणा में पैदा हुआ है, कितना मध्य प्रदेश में हुआ है और कितना उत्तर प्रदेश में हुआ है जब हर प्रान्त खुद के लिए सोचता है तो हर एक जिला भी खुद के लिए क्यों न सोचे? मैं केरल में गया था। वहां पालघाट का चावल कोज़ीकोड नहीं जा सकता है। जब एक बार हमने स्वीकार किया कि प्रान्त से प्रान्त में न जाये तो फिर उसकी कोरोलरी यह है कि जिले के बाहर क्यों जायें, फिर तहसील के बाहर क्यों जाये और आखिर में किसान कहेगा मेरे खेत से खलिहान और खलिहान से बाहर कहीं न जाये। जो पैदा करता है वही उसको रखे। जब वह पूरे देश के लिए है तो पूरे देश के लिए आप राष्ट्रीय नीति रखें, बन्दी हटे और बाजार भाव से किसान का माल खरीदा जाए। इससे किसान के मन में विश्वास पैदा होगा कि खून पसीना करके जो वह पैदा करता है उसकी ठीक कीमत आज बाजार के अन्दर उसको मिलती है। जनता को आप सुविधा पहुंचायें, आप जनता को अनाज सबसिडाइज करके दे सकते हैं अगर यह प्रान्त बन्दी चलती है तो इसका मतलब यह है कि मां का जो चित्र है वह ठीक ढंग का मूर्त चित्र हमारे सामने नहीं है। भग्न मूर्ति की पूजा नहीं होती है। अन्तःकरण की मूर्ति भग्न करके पूजा करें तो उसी का नाम है अनाचार, व्यभिचार मैं नहीं कहता हूं। यह दल बदल अनाचार है, आचार नहीं है। कुछ भी करने के लिए अगर आदमी प्रवृत्त हो जाता है तो उसको रोका जाना चाहिये।

इन शब्दों के साथ मैं इस अविश्वास के प्रस्ताव का जो यहां पर आया है पूरी तरह से समर्थन करता हूं।

श्री भोला नाथ (अलवर) : अविश्वास का जो प्रस्ताव आया है उसकी मुखालिफत करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। इसका कारण यह भी है कि जो भी माननीय सदस्य अभी यहां पर बोले हैं, विरोधी पक्ष के बोले हैं उन्होंने स्वयं ही एक दूसरे की बात को काटा है। उनके सामने न खुद की कोई नीति है और न कोई कार्यक्रम है, कोई प्राग्रोम है। अभी जोशी जी बोल रहे थे। कम्युनिस्टों को वह खरी-खरी सुना रहे थे। लेकिन आप देखें कि जिस समय इस प्रस्ताव को रखने का समय आया था उस समय यह और इनकी पार्टी के सभी सदस्य खड़े हो गए थे। तब रंगा साहब भी खड़े हो गए थे, उनकी पार्टी के सदस्य भी खड़े हो गए थे जो कि सब से ज्यादा कम्युनिस्टों की बुराई करते हैं। किसानों का पक्ष लेकर वह कह रहे थे कि किसानों के लिए इस कांग्रेस गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया। वह कभी-कभी राजस्थान का भी जिक्र करते हैं। मैं रंगा साहब को बतलाना चाहता हूं कि राजस्थान के अन्दर कांग्रेस ने किसानों के लिए जो कुछ किया है वह शायद किसी अन्य प्रान्त में नहीं किया गया है। वहां राजा महाराजाओं को समाप्त किया गया है, विसवेदारों और जागीरदारों को खत्म किया गया है और सन् 1955 में ही काश्तकार को ज़मीन का मालिक बना दिया गया है, 1947 के बाद जो ज़मीन उसके पास थी वह उसका मालिक बन गया है। उसको ज़मीन का कब्ज़ा दे दिया गया है। यह काम वहां पर कांग्रेस ने किया है। मधु लिमये साहब कह रहे थे कि सन् 1952 में कांग्रेस का बहुमत नहीं

[श्री भोला नाथ]

था। उनको शायद इस बात की जानकारी नहीं है कि उस समय भी कांग्रेस बहुमत में थी। उसी समय कांग्रेस ने तय किया कि जागीरदारी को खत्म किया जाए, विसवेदारी को खत्म किया जाए और काश्तकारों को जमीन का मालिक बनाया जाए। राजस्थान में ही अन्य सभी राज्यों की तुलना में सब से अच्छी लैंड रिफार्म्स हुई है। राजस्थान में स्वतंत्र पार्टी का सब से ज्यादा जोर माना जाता है। स्वतंत्र पार्टी की महारानी जी और रंगा साहब पक्ष तो किसानों का लेते हैं, नाम तो किसानों का लेते हैं लेकिन सबसे ज्यादा विरुद्ध काम वहां पर वे किसानों के ही कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि वहां पर बड़े-बड़े प्लाट्स बनाये जाय, बड़े-बड़े फार्म्स स्थापित किये जायें और यह जो सीलिंग लगी है इसको खत्म किया जाए।

कांग्रेस जो बात कहती है उसकी निन्दा की जाती है, उसका विरोध किया जाता है लेकिन आपका कौनसा कार्यक्रम है जो सामने रखा है, कौनसा प्रोग्राम है जो सामने रखा है ताकि उस पर जनता ध्यान दे सके और उस पर अमल कर सके।

बार-बार राजस्थान का जिक्र आता है। यह कहा जाता है कि वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। आपको मालूम ही है कि किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति का शासन वहां लागू हुआ था। उसके लिए विरोधियों ने मांग की थी, पार्लिमेंट के सदस्यों ने मांग की थी और कहा था कि वहां राष्ट्रपति शासन लागू किया जाना चाहिये। उस समय वहां पर दफा 144 थी। महारानी गायत्री देवी ने यह मांग की थी कि उसको हटा लेना चाहिये। दूसरे आपके लोगों ने मांग की थी कि इसको हटा लेना चाहिये। दफा 144 को वहां हटाया गया। उसके बाद वहां पर दंगे हुए। फिर जो कुछ घटनायें घटी वे आप से छिपी हुई नहीं हैं, वे सर्वविदित हैं। कल अटल बिहारी वाजपेयी जी कह रहे थे कि हम क्यों बंगाल में एकशन नहीं लेते हैं। जब एकशन लिया तो आज वह इस अविश्वास के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए खड़े हो गए। इस तरह की जो बातें हैं इनको देखते हुए कैसे आप लोगों पर विश्वास किया जा सकता है? कैसे यह कहा जा सकता है कि आप सही तरीके से व्यवहार करना चाहते हैं, सही रास्ते पर चलना चाहते हैं।

हमारे उधर बैठने वाले माननीय सदस्य कहते हैं कि प्रोडकशन गिर गया है। प्रोडक्शन को किसने गिराया है, यह मैं उनसे ही जानना चाहता हूं। कम्युनिस्टों ने ही तो गिराया है या फिर उन सरकारों ने गिराया है जो कि संयुक्त दलों की सरकारें हैं। किस तरह से प्रोडक्शन गिरा? बंगाल में कैसे गिरा। आप जानते ही हैं कि बंगाल में राजस्थान के बहुत से लोग जाकर बसे हुए हैं और वे कलकत्ता के आस-पास इंडस्ट्रीज के मालिक हैं। लेकिन आज वे वहां भयभीत क्यों हैं? क्यों वहां से वे निकल रहे हैं? क्यों वे चाहते हैं कि दूसरी जगह जा कर वे अपनी इंडस्ट्रीज को जमायें? जो नीति वहां सरकार ने बरती है उसी का यह परिणाम है कि प्रोडक्शन गिरा है। प्रोडक्शन गिरता है उस वक्त जब देश की आर्थिक अवस्था गिरती है, देश की हालत बिगड़ती है। वहां पर घेराव किये गये और लोगों को भयभीत किया गया जिससे लोगों के मन में आशंका पैदा हुई। इससे न केवल प्रोडक्शन गिरा बल्कि जो नई इंडस्ट्रीज खोली जानी थीं वे भी वहां खोली जायें या न खोली जायें, इस पर लोगों ने दुबारा विचार करना शुरू किया। जब कोई नई इंडस्ट्री खोली जाती है तो खोलने वाले के सामने यह चीज आती है कि सरकार ये जो घेराव हैं इन पर कंट्रोल पा सकती है या नहीं, सरकार उनके लिए सुरक्षा का प्रबन्ध कर सकती है या नहीं। जब वह देखता है कि वह नहीं कर सकती है तो ऐसी हालत में वह उस जगह नई इंडस्ट्री को नहीं खोलेगा और जो खुली भी है उसको भी जरूरी हुआ तो अन्यत्र ले जाएगा। इस तरह से प्रोडक्शन तो गिरेगा ही। इसके लिए बंगाल की सरकार खुद जिम्मेदार है।

बंगाल में इस समय जो कार्रवाई की गई है वह देश के लिए एक बहुत बड़ी मुक्ति का काम है। कल कहा गया था कि एक बड़ी महामारी फैल गई है डिफैकशंज की। एक बहन ने तो यहां तक कहा था कि यह कैंसर की बीमारी है। मैं मानता हूं कि यह महामारी है और यह महामारी शायद आज भी खत्म नहीं हुई है। आज ही पंजाब के अन्दर सतरह आदमी डिफैक्ट कर गए हैं और इससे घबरा कर वहां के चीफ मिनिस्टर श्री गुरनाम सिंह ने इस्तीफा दे दिया है। इन सब बातों से यही जाहिर होता है कि हिन्दुस्तान के अन्दर सिवाय कांग्रेस के आज भी कोई ऐसा दल नहीं है जो शासन को चला सकता हो। जो परिस्थितियां उत्पन्न हो रही हैं वे इसी की ओर संकेत करती हैं। आज नहीं तो कल दुनिया पहचान जायेगी कि उसे उसी रास्ते पर चलना है जो रास्ता कांग्रेस ने बताया है। लोग भी अपनी इस गलती को महसूस कर रहे हैं कि कांग्रेस के खिलाफ जो उन्होंने राय दी है ऐसा करके उन्होंने गलती की है।

राजस्थान का बार-बार जिक्र आता है और सोने के बारे में वहां जो काण्ड हुआ था उसका जिक्र किया जाता है। अभी बनर्जी साहब कह रहे थे कि महामाया प्रसाद जी का नाम नहीं लिया जाना चाहिये। हमारे मधु लिमये साहब से जिन्होंने इस अविश्वास के प्रस्ताव को पेश किया है, मैं पूछना चाहता हूं कि वह सोना ही सोना क्यों पुकारा करते हैं? सोना उनकी जेब में नहीं आया। जिसका सोना छोड़ा गया वह उन की पार्टी का आदमी नहीं था। वह गत चुनाव में कांग्रेस के खिलाफ लड़ा था और कांग्रेस के हाथों उसकी हार हुई थी। वहां से हमारे ओंकारलाल बोहरा जीत कर आए हैं। वह सोने वाले को हरा कर आए हैं। सोने के मामले के ऊपर वर्डिक्ट आफ दी पीपल मिल गया है। अगर गोलमाल हुआ होता तो चीफ मिनिस्टर को वहां हराते लोग, कांग्रेस को लोग हराते, चित्तौड़ में उसको हराते। जब कोई इस तरह की खरी बात कही जाती है तो आप नाराज हो जाते हैं। लेकिन ये लोग दूसरों पर उंगली उठाने और उनको बदनाम करने में नहीं हिचकते हैं। राजस्थान के बारे में चाहे जो कुछ भी कहा जाये, लेकिन अगर माहामाया बाबू के बारे में कुछ कहें, तो वे नाराज हो जाते हैं। मैं अपने मित्रों को कहूंगा कि वे अपना मुंह शीशे में देखें, जिससे वे बात करते हैं।

बंगाल में जो कुछ हुआ है, सब उसको जानते हैं। आज कहा जा रहा है कि अनाज नहीं मिल रहा है, चावल नहीं मिल रहा है, परेशानी पैदा हो गई है, लेकिन बंगाल का हर एक आदमी इस बात को जानता है कि जब श्री पी० सी० सेन की हुकूमत थी, तो उस वक्त डेढ़ रुपये किलो चावल मिलता था, जब कि आज चावल पांच छः रुपये किलो के हिसाब से मिलता है। सब लोग इस बात को जानते हैं। मैं अभी स्पाट न्यूज़ को देख कर आया हूं कि बंगाल के लोग शान्ति बनाए हुए हैं, क्योंकि वे समझ रहे हैं कि यह उनकी मुक्ति का दिवस है। कल हरियाणा के लोगों को मुक्ति मिली है। पंजाब के लोगों को श्री गुरुनामसिंह से मुक्ति मिल रही है। हो सकता है कि बिहार के लोगों को जल्दी ही महामाया प्रसाद सिंह से मुक्ति मिल जाये। विरोधी दलों ने संयुक्त दल और क्रान्ति दल आदि के नाम से जो भानमती का कुनबा जोड़ा है और हुकूमतें बनाई हैं, वे सब अपने-अपने रास्ते पर लगेंगी।

श्री रंगा ने कहा है कि श्री पी० सी० घोष के साथ केवल 17 आदमी हैं, लेकिन फिर भी उनको गवर्नमेंट बनाने का मौका दिया गया। लेकिन क्या उनको मालूम नहीं है कि मध्य प्रदेश में क्या हुआ? वहां पर जो लोग कांग्रेस से डिफेक्ट कर के आए उनको गवर्नमेंट बनाने का मौका दिया गया। राजमाता ग्वालियर ने गवर्नमेंट को जायन नहीं किया, बल्कि डिफेक्टर्ज को गवर्नमेंट बनाने दी। हमारे मित्र मध्य प्रदेश के बारे में तो जिक्र नहीं करते हैं। लेकिन अगर बंगाल में इस तरह की गवर्नमेंट बनती है, तो उसको मिसाल

[श्री भोला नाथ]

हमारे सामने रखते हैं। आश्चर्य की बात यह है कि बहुत पुराने पार्लियामेंटेरियन और नेता इस तरह की बात कहते हैं।

मेरा निवेदन है कि अगर विरोधी दल के माननीय सदस्यों को वास्तव में सही तरीके से कोई बात कहनी है, तो वे एक मत से और एक विचार-धारा के अनुसार कहें। चूंकि माननीय सदस्य कई स्वरों में बोलते हैं और परस्पर-विरोधी बातें कहते हैं, इसी लिए देश उनसे परेशान हो गया है और इसी लिए संयुक्त दल की सरकारें खत्म हो रही हैं। रंगा साहब एक भाषा में बोलते हैं और जोशी साहब दूसरी भाषा में बोलते हैं। हिन्दुस्तान के लोग यह सब कुछ देख और सुन रहे हैं। वे जानते हैं कि इनके हाथ में क्या अधिकार देना चाहिए और ये कहां तक उसके योग्य हैं। वे यह भी जानते हैं कि जिस सरकार को ये बदलना चाहते हैं अब तक उसने क्या काम किया है और उसका रिकार्ड क्या है।

इन दलों को सरकार चलाने के लिए आठ नौ महीने का मौका दिया गया, लेकिन ये सरकारें ताश के पत्तों के घर की तरह गिर रही हैं; दिन में दो-दो गवर्नमेंट्स गिर रही हैं। जिस सरकार और जिस पार्टी के खिलाफ़ ये लोग अविश्वास-प्रस्ताव लाए हैं, उसने बीस वर्ष में काम करके दिखाया है, देश का इन्टेग्रेशन किया, देश में एक ऐसा माहौल पैदा किया कि यहां पर भी—इतने बड़े मुल्क में भी, पचास करोड़ के मुल्क में भी, डेमोक्रेटिक राज्य, प्रजातंत्र, चल सकता है। किसी मुल्क ने आज तक इतने बड़े इलैक्शन नहीं कराए। इस सरकार ने इस देश में चार इलैक्शन स्वतन्त्र रूप से कराए, जिनमें सबको भाग लेने का मौका दिया। लेकिन उसकी कोई तारीफ़ नहीं है। हमारे मित्र बतायें कि कांग्रेस के अलावा किस सरकार ने आज़ादी के बाद चार इलैक्शन कराए हैं। विरोधी दलों को उन इलैक्शन्ज़ में भाग लेने का मौका दिया गया, गवर्नमेंट बनाने का मौका दिया गया। उसके बाद जब वे फेल होते हैं, तो उसका दोष हम पर मढ़ते हैं, अविश्वास-प्रस्ताव लाकर अपना गुस्सा उतारने की कोशिश करते हैं, कोई दूसरी नई पालिसी या प्रोग्राम नहीं लाते हैं।

इन शब्दों के साथ मैं इस अविश्वास प्रस्ताव का घोर विरोध करता हूं।

SHRI S. A. DANGE (Bombay Central South) : Sir, I rise to support the motion moved by my friend Shri Madhu Limaye. The reasons which I wish to give for supporting this motion of censure against the Congress Government are not going to be very formal. I do not want to go into the formal aspect, the constitutional aspect of that question, because only a few days back the problem of the powers of the Governors was argued, the problem of the rights of ministries was argued and the problem was put on a proper footing.

At that time also there was more or less an expectation or fear in the minds of the people that in spite of the arguments that were advanced on behalf of the opposition and even on behalf of certain democratically minded people who may still be left in the Congress Party, that such an attribution of dictatorial powers to the Governor would be to the detriment of democracy in this country. But, then, after two or three days, we find that the Governor of Bengal, had a doubt whether Shri Ajoy Mukerjee with his 157 or 154 votes had a majority or not. Even taking it for granted that 17 had defected, even then, he had certainly more than 130 of the Congress Party, and the Front still continues to be the largest single party.

I would have expected the Governor to interpret democracy rather liberally and properly, by saying that there is another party which is the largest party, that is, the Congress Party, next to the Front. It has secured a majority, of which he is convinced and he is therefore dismissing this Ministry. Did he come to that conclusion? No. The conclusion that is before us is that a Chief Minister with 15 members has a larger majority than a United Front Ministry with 142 votes. This is the wonderful arithmetic of democracy which exists today on the other side.

Now let us consider an honest proposition. That the Congress members, along with P.C. Ghosh defectors or others had formed majority and said "we are a major party or a major combination" and, therefore, the minority government is dismissed, that I could have understood. But the Governor did not give them an opportunity even to call the Assembly. The doubt about the majority of the United Front Ministry is replaced by conviction of a majority of a Chief Minister with 15 votes. What more ridiculous interpretation could there be of democracy, constitution and all that.

If they had demolished the Ministry on the ground of law and order, that at least I could have understood. But they dare not do that, because there was law and there was order. In fact, things were improving because the employers, landlords and other interests concerned were coming to realise the fact that certain demands of the people have got to be conceded. In fact, a tripartite meeting on the question of industrial relations was being proposed and things were moving in a better direction.

AN HON. MEMBER : From bad to worse.

SHRI S. A. DANGE : Not only that. The food situation was promising to improve in view of the coming harvest. But it is just that that frightened them, that if the food situation improves and this ministry succeeds in solving that problem by proper procurement, then, in that case, they would have no chance of coming to power. So, this was the only chance to dismiss that Ministry, and they dismissed that Ministry in the most arbitrary way.

Now, they have taken another precaution. I must say that there are very good tactitians in that party. They are not dull-headed, as some of us think; no, they are very shrewd. Some of us will charge them of dismissing a Ministry which frankly took the side of the working class, the peasantry and the middle class. So, they said "no, we have dismissed the Haryana Ministry" and the people do not know which class it represents. It certainly does not represent the working class and the peasantry. They dismissed one Ministry, which is difficult to be described, because of defections, because of want of a programme and they dismissed another Ministry, West Bengal Ministry, which frankly is led by the Communist element. There is no doubt about it.

16.40 Hrs.

[MR. SPEAKER *in the Chair*]

It is a United Front Ministry but we do not deny the responsibility that we carry there in decisive weight as a Communist Party. In this respect I can even mention my other comrades in the Communist Party (Marxist) We are the driving force, the leadership, in that United Front Ministry along with other parties who agree on a common programme to carry out certain things. Therefore, you could say that this was frankly a ministry leaning on the side of the working class, the peasantry and the middle class and therefore you did not like it.

Then, you would counter the argument by saying that Haryana Ministry is dismissed and now Punjab Ministry is going; therefore we cannot blame you. No, Sir; we have to blame. Why ? Because you want to achieve a certain thing. What is that certain things ? I do not want to go, as I said, into the formal aspect nor while discussing the subject I would refer to a wider range of subjects of foreign policy or other policy because let us stick to the problem that certain non-Congress ministries came into existence and you are uprooting them. The other questions of policy and other grievances we might put up on a later occasion.

Similarly, I do not want to counter the arguments of certain friends on this side, who found it convenient to attack the Communist Party while supporting the motion. I think, that is not good tactics to start firing in the Opposition benches itself when a common fire should be directed against the ruling party. In any case, that means that the Opposition has yet to really evolve agreed tactics. Not that they have better tactics; they fire against each other in a private way, in the AICC or somewhere or other. There they behave more or less under a *danda* properly exercised. Now, we have not got that advantage of the *danda* properly exercised even in a democratic way. So, this thing happens. But they need not be very jolly about their affairs. Ultimately all the parties agree that they do not deserve to continue in their role.

[Shri S. A. Dange]

Now, I want to discuss one or two things rather more seriously instead of just hurling abuses and so on. They are commonly known. The question is why this phenomenon of non-Congress ministries arose at this time and why there is such an unseemly hurry to dismiss those non-Congress ministries. The rise of the non-Congress ministries is a culmination of a historical process of 20 years' rule of the Congress.

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI Y. B. CHAVAN): You mean, the non-Congress ?

SHRI S.A. DANGE: Yes, non-Congress.

The rise of non-Congress ministries is a criticism of the people made from a common standpoint, not the Communist, not the Socialist, not a particular party but in fact there are the Jana Sangh, the Swatantra, the Communists, the Socialists and all. But the voter had a criticism to make, "gentlemen, your policies for the last 20 years have not gone in the direction in which you promised to go", and therefore they prefer that some others be given a trial with a new programme or perhaps the same programme even to see whether they would deliver the goods properly or not; and if they did not deliver the goods properly then they shall find a third method. That was the reason why nine States more or less voted against the Congress and you got non-Congress ministries.

Why was this criticism voiced? Those points are very common but let me mention them. There was the promise of socialism. There may be differences on the definition of socialism. We may define it according to Karl Marx; you may define it according to Mahatma Gandhi. Now somebody may define it according to Jawaharlal Nehru or you may start defining it according to the definition of my Home Minister friend, Shri Chavan or Shri Morarji Desai or any body. But there was some common understanding that this country, after independence, ought not to go in the same way in which the Western mperialists have gone, develop monopoly capital, keep these landlord interests safe and take a path which ultimately leads to the same crisis as in Europe or in America. That was the general desire. So, we evolved a certain common programme though we had our criticism. I am not going to repeat the arguments which I have already made. I do not want to do that in this House, but then it is necessary to remind you about it. Having done that, you undertook even in the initial stages some nationalisation measure which hurt, no doubt, certain interests but then you persisted and there was some development which we criticized, no doubt, because the wealth that was generated did not go to the peasantry, the working class and the middle class. But still a certain direction of building a State sector of economy, a certain abolition of zamindary interests, a certain scaling down of rent and revenue—all these things were promised and were being carried out. But the natural law of capitalism was bound to persist, assert itself, and monopolies developed. We came out with the criticism of monopolies; you came out also with the partial criticism of monopolies. It is the Congress Party, which appointed the Monopolies Commission. It is the Congress Party which got Dr. Hazari to make a report. What was proved? It was proved that your policies had gone wrong, that monopolies had concentrated, that they had got possession of all the means of life in this country, that agriculture had not developed for the simple reason that land reforms were not carried out. Mr. Asoka Mehta and others who were dealing with the Planning Commission's Report on Land Reforms proved that you did not carry out land reforms. Therefore, the production of food was falling and you got into the trap of PL 480 and the more wheat you got, the more the peasant was killed here and agriculture suffered instead of growing at the rate at which the country needed. It is not that it is not growing —2½ per cent population growing, 2 per cent agriculture growing.

This is the thing which was revealed. 75 business houses cornering 50 per cent of the capital; nearly Rs. 3,000 crores of liquid capital in the hands of 5 banks—what kind of banks ?—uprooting every scheme of yours that they don't like and you, ultimately, forced to surrender, and some of you surrendering, just for the mere exchange of donations. I do not blame everybody; I do not want to name everybody. But the general pattern was: if there was a criticism of monopoly, Rs. 1 crore; if there was more criticism.

Rs. 5 crores; if there was a still more heroic resolution of abolition of privy purses, still more crores of rupees; and if there was a decision to nationalise banks, those Rs. 3,000 crores at your disposal with the prayers—for God's sake, don't carry it out".

This is continuously the betrayal of the common man, who believed in you. I cannot say he did not vote for you. You have got a majority here. I cannot say he did not vote for you in the previous elections and gave you a majority in all the States. I do see it; everybody sees it. It does not require any clever man to say that. Why was it happening? That was because he still believed in you, because you manoeuvred clerverly between his criticism on one side and the continuation of the same policy on the other side and the common man could not see through the game that while, on the one hand, you were building the States sector on the other hand, Birlas and Tatas were growing. You said, you take both and some day this will swallow that. But that is following this. That started becoming apparent and even your historic step for the abolition of privy purses is being carried on by means of negotiations and scaling down of their whisky bottles and import permits. That also is going along in the case of the nationalisation of banks.

My friends, I want to tell you that it is the betrayal of promises, the continuous receding from the policies which you had enunciated which we criticised as half-way house—there was some house at least—but now the whole house is demolished. Therefore, the electorate said, "We must topple them." Hence, they voted against you in 9 States. By whatever combinations it may be, the discontent was organised by several parties and all agreed on one point to defeat the Congress. We may quarrel. we may abuse each other; we may have different programmes and all that. But there was this thing, the masses moved. Why did they move? They moved because the monopolies are still there, the landlord interest is still there. When we want to abolish land revenue, there comes a Minister saying that the historic system of taxation, handed down from what days, I do not know, must be adhered to. Therefore, the discontent was organised, took the form in the elections of voting against you and these Ministries came. What should have happened to the Congress Party ? I am no adviser to you; I do not propose to advise you because I do not think that you are now capable of being advised by anybody. (*Interruption*) The last step is finished. Some of my friends might have accused me of being a revisionist or a reformist or a moderate and all that, but how are the events proceeding? It is always good to retain some hope in the commonsense of man because there are men inside that Party also. I have not given them up for lost completely, though I have no desire to form any coalition with them or have defections. No, I do not want that.

When these things happened, when the people voted against you, I thought that there would be some review of your own thinking; may be, some criticism amongst each other, may be there were right or left or central groups amongst yourselves, but then I want to know what happened to them ? What happened is yesterday's decision to topple all the Ministries. Who has won? That wing, that line of thinking has won which wants to topple any democratic criticism of the monopoly line, any democratic criticism of the pro-landlord line, any democratic criticism of the anti-people line. That group has won which said, "No, shut this out completely; otherwise we and everything that stands with us, *i.e.*, monopolies, are gone". What is the use of repeating the donations that the *cementwalas* and *sugar-walas* are making ? Everybody knows that. My friend, Mr. Madhu Limaye is an expert in getting all these lists to you at any time. Why do these things follow ? Monopoly capital is the source of corruption and no amount of moral lecturing on anybody's part will cure you of corruption, collective or personal or Ministerial or at whatever level it may be. They can buy and, therefore, what happened ? Monopoly decided, "Disrupt non-Congress Ministries". Naturally, those who had no programme, those who had no gutts, those who had no clear thinking, those who had no perspective of this country developing into a socialist one, could be bought, and that buying phenomenon is the defection. Very rarely you find honest defections. Honest defec-

[Shri S. A. Dange]

tions took place before the elections. After the elections, most of the defections are the expression of the same phenomenon, which has ruined the Congress Party, which has ruined the economy of this country and which has ruined the common man. Therefore, I do not support these defections even if they were to give me a majority; I do not want a defector to come to me and give me a majority. I want to stand by a programme; that programme has to be fulfilled and if, for that programme, I have to stand alone, I want to be alone because I have confidence in the masses; the masses' programme will be for me and not the programme of a Party. Therefore, what we tried was to form Fronts. People laugh at 'Fronts'. We do not want the exclusive rule of the Communist Party. Are we charitable? I am not charitable for the simple reason that the people of this country are not yet convinced that the Communist Party line alone is the correct line; therefore, I bowed down to the criticism even of the Party. Therefore, we said, "Shall we agree on any common thing? Shall we have a Front?". And now the Front idea has been accepted. But that does not mean that I do not have a programme I do defend my Party; I do defend the West Bengal Government and what it did; I still do defend the statement which somebody referred to but did need not name me. It was my statement, "The High Court judges also will have to be gheraoed". It was a shocking statement. I know that. Some people say that I have got in some quarters, an unmerited reputation of being reasonable. Well, I am reasonable, but at the same time I do stick like hard steel to certain things which I believe in. The judiciary in this country is not dependent on any abstract law and there is no such thing as an abstract law in any society.

Law is always the expression of the class that rules. It is not an expression of the Judges or their honesty or their belief. No, the law reflects the rule of the class. Manusmriti laid down—I do not want to quote Sanskrit in the presence of Mr. Jagannatha Rao—that the evidence of the Brahmin alone shall be believed without question. The evidence of the Kshatriya will be believed with a question, the evidence of a Vaishya will be doubted and the untouchable shall never be allowed to give any evidence in a court of law. A whole section of the society was thus dis-enfranchised. And an exception was provided that only an untouchable, who has reached the age of 80 and over can be allowed to come and give evidence. Over 80—that means that for 80 years he must prove his loyalty to the ruling class and then alone he can be considered to be truthful. To-day that rule is gone, but the spirit remains the same, the spirit that when a rich man comes to the court, even the Judges try to get up, give him a chair, ask him whether his health is all right, and if he has a headache, with an aspirin, they say 'Give him a chair'. But when a labourer in tattered clothes comes to the court, then the Police shouts at him and the Constable runs at him. He says 'No, I have come to give evidence'. 'Then, stand erect', shouts the Judge. Have I not seen that? For forty years while working for the working classes in this country, I have seen what happens to the workers when they are hauled up before the courts and how the Judges behave. I have seen in the National Labour Commission of which I am a Member how the respectable Judges and others behave to witnesses who come in tattered clothes, ordinary workers and how they behave when others come with wonderful ties, in tip-top dress or with a Gandhi cap and so on. Do I consider this an impartial system? Apart from that, the Judges are bound down. Certain property concepts are inherent in the Constitution and they are bound to them. Therefore, if the just cause of a worker is not accepted and if the High Court rules that it shall arrest a worker under the Preventive Detention Act for a gherao, then I say 'You are as much an instrument of the ruling class as anybody else and, therefore, I shall have the right to gherao you also'. It is no question of disrespect to the judiciary. It is the concept of class law. Please understand this. In your Constitution it is embodied.

What are we doing in Bengal? What did we do that we deserve to be abused? In Naxalbari?—Yes. The essence of Naxalbari was a demand for possession of land from which eviction has taken place. I frankly differ from the thesis of Naxalbari. But I am not here to discuss the thesis between the two of us; No, not for your benefit or for your advice. But, ultimately, when some hundreds peasants come with bows and arrows, you make

such a huge thing out of: Peking radio talked about it. Can just a Peking radio talk about it defeat our country ? Only by such talk can only any Party grow in this country? It cannot. Unless a talk has roots in the thinking of the people, in the masses of the people, no amount of Peking shouting is going to corrupt the masses of this country to run in favour of the thought of Mao Tse-Tung. Nothing is going to happen. Why do you make so much about Peking radio? In spite of Peking radio, did not people in this country defend the country in 1962? Did not the Communists defend the country ? Therefore, you used first Naxalbari; then came the Gurdwara agitation and then Hindu-Muslim rioting. You tried all sorts of all methods to start a law and order situation to topple that Government, but you did not succeed. No doubt, the Front Parties were divided. You thought their division might help you.

SHRI BUTA SINGH (Rupar) : Gurdwara agitation was somebody else's game.

SHRI S. A. DANGE : The question was that our differences, it was thought, might help the Congress Party to defeat the Government. They were composed, an agreed line was being followed and when it was clear now that the Government might remain stable, you intervened. Therefore, what I am putting forward is a simple thing. On what ground do you dismiss us? Our performance in favour of the peasant is well known. You may say that we beat some landlord or we beat some rich peasant. If so, please arrest us and try us and give us the punishment. Or you may say that 'You beat some worker or some manager'; if so, arrest and give us the punishment.

17 Hrs.

But the fundamental point was that the peasants were being deprived of their natural dues. What have you done about it? You may, of course, ask us 'What have you done about it?' We in practice were encouraging the peasant and telling him 'Please do not give the jotedar the 75 per cent which he demands'. This is what we tell the worker. The wages in Bengal, you should know, are something like 20 to 30 per cent lower than in Bombay. Why is that so? The entrenched capital of Birlas, the tea planters and the mine-owners were not shaken so far any trade union movement, an unfortunate fact of history. But we in Bombay during the last 30 years beat them down like anything, right from British days till now. We had wonderfully organised strikes there and we were able to raise the wage level. It is not that the wage level there is sufficient or that it is such as would not create any discontent. But the point is that there is some order and some kind of organisation there. There is some acknowledged industrial relation in the factories in Maharashtra and Bombay. It is not due to the philanthropic Congressmen at all, because the Congressmen are there in Calcutta and also in Punjab and nothing has happened in those two States, but it is due to the fact that we in Bombay had disciplined the workers by a furious strike struggle.

Somebody may ask 'Why did you not discipline the Calcutta employers' ? Sir, there are differences between States and States, between blocks and blocks of working classes, between blocks and blocks of leaders and so on. I find my hon. friend Shri J.B. Kripalani murmuring something. I may tell him that I am not going to discuss the history of the trade union movement now. As to why it did not happen in Calcutta, we could discuss it later on. What I am discussing now is something else. It did not happen under you anywhere. So, it does not matter ! I am only saying that we, in the Communist Party, were the absolute leaders of all this discontent and organisation in the city of Bombay. And elsewhere, at that time this did not happen. There was discontent, and in the factories people asserted 'This is the norm that should be followed', but employers would not follow it. But ultimately they have had to follow it.

See what is happening in the public sector. I was there yesterday at Hardwar and that was why I was not here to speak about Haryana. There was a strike there. A wonderful turbine plant is coming up there. 7000 people went on strike. Why? They had not been given the Gajendragadkar Commission's award; then the employers agreed and said 'Yes, we shall give you'; then they were not given the wage board award; again, the employers agreed and said 'We shall give you'. But the strike took place all the same, because

[Shri S. A. Dange]

there was no rule of promotion, no rule for settlement or anything of the kind, and the management believed that they could make the three unions quarrel and go on. Ultimately, all the three unions united and had a strike. So, it was settled ultimately. And we intervened and did the thing. Why should this happen?

Again, why was there a strike in Bhopal? Why is there a strike in Bhilai? My hon. friend Dr. Chenna Reddy on the other side has himself admitted that 'For God's sake, give us some procedure of recognising a union which has got the backing of the workers'. Ten years have gone. My party had given a slogan 'Recognition by ballot'. I was ridiculed and told 'Ah, recognition by ballot?' I was asked 'Ballot of all workers?', I said 'Yes, of all workers.' Why should they not agree to this? You could elect a Minister, a Chief Minister and the Prime Minister by ballot, but you can not elect your union by a ballot!

Now, what has happened? After ten years, the lesson has been learnt after so many sacrifices. The INTUC is recognised in Durgapur, the INTUC is recognised in Bombay. We called for a strike. The strike was complete. That was a ballot. They said 'No, no, strike is nothing'. The strike was there because they demanded three months' wages and you asked for six months' wages. Therefore, they had also struck along with you'. I said 'All right, you demand nine months' wages and try', but they would not do it.

So, ultimately, the result is this, and let me inform you of it. The mill-owners in Bombay, through their representative Mr. Naval Tata have agreed to this. Mr. Naval Tata said 'For God's sake, if this unrest can be resolved, all right, I agree to your ballot'. There is panic among the ranks of the employers. They gave evidence before the National Labour Commission saying 'We agree to the ballot, because we think that that is the only solution now.' Why were ten years wasted?

Why is Chenna Reddy still wasting time in the three or four steel plants where there is still trouble going on? Because he insists that Congress unions must be recognised.

Therefore, I am saying that your approach to the problem is wrong, your development of 20 years has brought retribution for the sins of the wrong policies. Those wrong policies were criticised by the masses in the form of nine non-Congress Ministries. It is not a criticism by the Communists alone. When the Swatantra got elected, some thought that certainly was no criticism, but I find that that also is some criticism. The Congress reaction was: borrow or buy defectors; topple by defections. Defections are creating an immoral atmosphere in the party politics of this country. Politics has to be based on party; there is no question about it. It is necessarily to be based on a party having a programme and trying to observe that programme. In the whole party relationship on which the politics of this country has to be based, you are bringing in a new element, that is, defection by bribery, by threats and all that.

Ultimately, what will be the result? I do not want to utter any threats. Now the Bengal Ministry has been toppled. You want to know where is the majority? Try to land in Calcutta today. Try. You will not succeed because there is complete closure. That is the verdict of the Bengal people against your most unjust action.

SHRI DWAIPAYAN SEN (Katwa): That is not correct.

SHRI S. A. DANGE: It is the verdict of the Bengal people against your dictatorship. No dictatorship will survive such unity of the people. You cannot divide the people by calling one Communist, another Marxist, the third a Naxalbarist and the fourth something else.

AN HON. MEMBER: CIA.

SHRI S. A. DANGE: We will not discuss CIA now. When you will be toppled by the CIA agents, then we will have a discussion, not now. The CIA has been toppling many dictatorships and ousting many others. There are many examples in other countries. Why be side-tracked into that?

Therefore, I say: Please take note. You may beat down the people in Bengal by calling in the Army.

AN HON. MEMBER: It is already there.

SHRI S. A. DANGE: But remember that one day the infantryman of the Army who is a peasant by his parentage, is also going to remember that. Do not think that always the commanders decide things. The infantryman also can decide. The artillery man can speak, the engineer can speak, and they are going to speak against —against you. You may ask 'Why are you so confident?' You may abuse my party as much as you like; you may abuse my Marxism as much as you like. But remember that from one-sixth of the world, it has come to nearly half the world, and the half is ultimately going to the full. There is no doubt about that.

You may topple any number of Ministries. You may put any number of Communists in Jail. You may shoot any number of Communists. It does not matter a damn thing because we know we are going to survive in this world and the world is going to be ours and not yours, of monopoly capitalism's.

I am not saying this of the Congress party. I am referring to the policy of a class. What instances can I give? Here are eminent economists who told us that devaluation is wonderful and it will save our economy, will increase our exports and imports. But exports went down, imports went down, everything went down, except the Minister who proposed it.

SHRI PILOO MODY (Godhra): He also went down slightly.

SHRI S. A. DANGE: The devaluation solution came from America. Then came the other, that wage freeze is the only solution. Freeze the wage of everybody, to begin with of government servants, and ultimately of everybody, except the Ministers. Seventy-five directors in this country are getting Rs. 3 lakhs per year. There was not a talk on the part of the Finance Minister of freezing or cutting down the directors' fees, but they want to attack our wages. Devaluation came from the World Bank, the wage freeze idea came from Mr. Wilson, from Britain. The two advices coelsced and the result is the ruin of the rupee. But here unfortunately they have a working class which is not led by the Labour Party of England. It did not accept the wage freeze. They in Britain accepted, and what happened? Nine lakhs of unemployed for Britain is not a small thing, and ultimately the £ was devalued, and they are in a mess as much as you are in a mess. Therefore follow the World Bank, follow the socialism of the Labour Party, follow the socialism of Wilson, devaluation and wage freeze. The result is you will be ruining the economy of this country, and we will have to save it by means of our organisation, an organisation based on unity of the democratic forces.

I still want all the democratic forces here to unite. I do not want only one party to go ahead, no. Therefore, these programmes are there. I have given you enough material to think over, but still yours is a no.

And naturally, the toppling is continuing. In some places you cannot do it, in Kerala for example. Very hard to try. Even when we had a majority of two in 1957, they could not even buy the two from us. The Inspector General of Police was sent to buy, his letter was caught, Rs. 2 lakhs were offered to two members, just two, so that they could topple the Ministry. They failed. I am thankful to Nehru. Though on many things I did not agree with him, there was one thing in him. At that time, before the election Shri T. T. Krishnamachari said that if these fellows get a small majority, we are not going to allow them to form a Ministry. Perhaps Pandit Nehru's daughter went to make speeches against us at that time. It does not matter. But when a majority of two came, that man—known for his world reputation and his reputation for being a democrat, in spite of beating down strikes and firing, he had some respect for democracy, some respect—he did not agree. Even with a majority of two, he said, they shall form a Ministry, and the Ministry was formed, which survived for 28 months, and when you could not buy our members, when there was no defection, what did you do? You started law and order, you started the people's liberation movement, led by all sorts of funny people, and you toppled the Ministry by raising law and order problem.

[Shri S. A. Dange]

I am giving this example to serve as a warning to my friends of the DMK, to the Kerala Ministry which exists now, as a sort of warning even to the Orissa Government, though I do not agree with them on many things. Don't think that if you have got a sufficient majority, these gentlemen will stop from toppling you, because they cannot survive except on the basis of absolute power of monopoly capital, absolute power of their rightist section, absolute power which draws support when they are tottering from international finance of monopoly capital.

So, the inevitable line that they are going to follow is this, and the inevitable end of it I do not know. I do not want to be a prophet, I do not want to give threats.

One inevitable end is a complete strike in Bengal. Bengal *bandh* has taken place. We are certainly going to rouse the masses throughout the country against the danger of dictatorship that is coming. Today even Mr. Setalvad calls it constitutional dictatorship. That will be followed by simple dictatorship. And that thing is there already, is coming, but it has got still a civil mask, because the more and more you try to buttress your order by calling in the troops the more and more, the troops, rather the commanders, will be tempted to think: if we have to save these gentlemen all the time, why not take it within our own hands? Simple logic. And then there will be the day when the Constitution also will be toppled.

So, disrespect for the Constitution to serve class ends of the bourgeoisie and the landlords in this country and to pacify certain foreign demands is not going to save our democracy. If you have any respect left for it, if you do desire that the Constitution's laws, its conventions, its fundamental rights, its contents, should really be translated into practice then respect democracy. When it says that monopoly must not take place, how is it you are violating that Constitutional provision? And still, you abuse, accuse us that we are violating the Constitution and taking to undemocratic measures. Then the result will not be good for the country. I am not saying not good for you only. It will not be good for everybody. That ultimately we will find a way out of it is certain. Otherwise you see what your indecision and bankruptcy of the policy is leading to?

My dear Chavan, I will address you: you are in charge of the tribal problems. What is being done there? The policy that this Government has is like this: it creates a problem, leaves the people quarrelling and then you sit on the top. When it comes nearer a solution, you create another problem and again sit on the top. They wanted to solve the Punjab problem; they came to an arrangement, as regards Haryana and Punjab. You put up Chandigarh in between for everybody to quarrel around and then sit on top. It is wonderful. This is the nice art of a magician who makes you believe that he has conceded a demand and yet, the thing goes wrong or something else happens as a result of which what has been achieved also goes to ruin.

What is happening in Maharashtra? We solved the problem of Maharashtra and Gujarat. Then, you put one point of quarrel of Belgaum around which the Maharashtrians and the Mysoreans go on quarrelling and you sit on the top. And Shri Mahajan walks in and says, "I will give you a solution." That is also no solution. You start the quarrel between Mysore and Kerala—whether this village or that taluk or that district of Karargode should go to one or the other—and then again you sit on the top! This sort of thing would not help. You tried that with regard to the tribals. And then you have armed Nagas. The Nagas did not believe in polite words. They said: as gentlemen, you do not concede; all right; we also do not concede. You will send the troops and resort to section 144; they say, we will have the guns and our 144, and for 10 years you are not able to stop them; it is ten years now. And the Mizos followed and the Khasis are going to follow; and the Mikirs are also going to follow. You are unable to solve the whole problem of the tribals because you try to impose on them your capitalist system, your norms, your methods of thinking. A State must have a Governor; a State must have seven Ministers and a State must have a big carriage drawn by four horses wherein the Speaker should go! And with all this, if we calculate the cost, you say to the tribals, who demand a State, "you are not viable." And if you are not viable, you are gone. After all, what is viability? Viability is based on the fiction of bour-

geoisie order. They have a wonderful forest wealth; they have got minerals and they have got oil and everything. Now, that is all grabbed by these gentlemen. What is left to them is a solitary bamboo with one small hut, and if they have got bows and arrows, about that also you create trouble. And then you ask them, "How can you form a separate viable State?" Then you tell the people, "if they want a separate State the others also want to share that wealth," and then you make them quarrel. Is this the talk you are going to have with them? This will ultimately result in what? They have got a border with Pakistan. You will say, "Ah, now you are speaking the truth." Yes. I am speaking the truth. The Nagas have got their weapons. When you try to reach them they slip away. Finished. You cannot do anything. Then, when they get confronted with your weapons, they slip away to Burma. How are you going to solve this problem? Are you going to solve this problem this way? The tribals are ours; the hill people are ours. Can't we demorcate in such a way that the interests of both are served and that both retain their independent identity in order to solve their problems? And if we as the Communist party from West Bengal go and preach to them and organise them and try to tell them that you can retain your land in spite of all these rich gentlemen from the zamindari, then, you say this is "Naxalbari, independent empire", and then the idiotic Peking Radio comes in. They are in a hurry to show that everything that happens in this world is a projection,—under Hinduism of the ancient *parabrahma*, and in the modern period, a projection of the new *parabrahma* called Mao Tse-tung! Why side-track things by such a thought? You are not going to gain thereby. The people are just immune to such things. When you shout against them, Peking Radio and all that, the people say, "What about us? What about the AIR" where they have formed a union and they want to get a basic wage of Rs. 200 or Rs. 300 a month. Somebody said here that the wages of the AIR artistes are lower than the wages of the municipal scavenger in the city of Bombay. With such an AIR, what kind of patriotism are you going to blare forth when the scavengers get more pay than the artistes of the All India Radio? Then naturally the Peking Radio is going to overwhelm you. In spite of all preachings of patriotism, there is such a thing as simple self-interest. In spite of all patriotism every Minister has to argue about his salary and allowances. That cannot be avoided.

My submission finally is this. I do not want to talk about other policies. I do not want to quote facts. Other policies are wrong. There is the foreign policy. I do not want to talk about it now.

SHRI SONAVANE (Pandharpur): Shri Dange is rather angry that the scavengers get more than the radio artistes.

SHRI S. A. DANGE: I am not angry that the scavengers get more, I am angry that the artistes and the culture which they represent get less. So it is better to be a man with a broom in the streets of Bombay than to be a man with a brain trying to sing beautiful songs on the radio to please the masses. That is your sense of values. I am talking about that (*Interruption*). Your criticism would be just if you were to say that the salary of the ministers should be less than that of the scavengers in Bombay. Then I can respect that democracy and criticism, not otherwise.

However, my point is this. Unless the basic policies are changed, this toppling of one or two ministries is not going to help. The masses are led on to revolt by such policies. We are bringing into contempt the whole system of democracy and the result will be that nobody will have any respect left for democracy. Then you will rely on law and order, and law and order never can survive the united revolt of the masses in a country because here law and order necessarily is based on exploiting interests of a certain class.

Therefore, what I would tell is this, let the governments survive on their own merit. If you want to test public opinion by all means we are ready to test public opinion any time. But then apply the rule impartially. Then the rule to be applied impartially is that rule which subsists in every democracy—the right of recall. Any representative elected who loses the confidence of his electorate should be liable for recall and that electorate should have the right to recall him. Are you prepared to accept that thing. The right to recall should be a fundamental right of democracy. When the masses lose faith in their representative who went on the basis of one programme

[Shri S. A. Dange]

and who the next day was found to be hobnobbing with Aminchand Pyarelal or somebody, then the masses should have the right to recall him. If a representative gets the confidence of the workers on the basis of a trade union programme and if he signs an agreement against the workers, the workers should have the right to recall him. You do not do that. If you want to have a really democratic principle of testing public opinion to be observed, please do it; we have no objection. We are prepared to test our following by means of elections any time. But this half-way house move of a fifteen-vote Chief Minister with 130 hiding behind him, not daring to acknowledge that they support him but quietly telling the Governor that they support him—some of them do not even dare to go to the Assembly; not that anybody is going to beat them because with Shri Swaran Singh's great army and Shri Chavan's great police force who can beat them; what is the use of beating them—that does not help. . .

SHRI PILOO MODY : And Shri Sheo Narain in Parliament.

SHRI S. A. DANGE : This kind of a ridicule of democracy should be halted, a real test be taken and the present ministry be again restored. If you want to do justice to the Constitution and democracy, start again, restore these governments as they were and have a trial if you like in any other democratic way that is provided for any in proper democratic thinking.

SHRI SHEO NARAIN : Have a telephonic talk with Shri Gurnam Singh today.

SHRI S. A. DANGE : I have not been able to follow the hon. Member. Any day, between Shri Piloo Mody and yourself you will lose—I step aside. Therefore, what I am saying finally is this, that these developments are going to lead to very unhappy events, because lives are going to be lost. The masses in Bengal are going to protest, and there is going to be a determined effort to see that no dictatorship is imposed on the people of Bengal. The workers are going to fight for their rights, whether it is President's Rule, or Mir Jaffar's rule, which you have supported just now, or misrule by 17 plus 130 with manifestos of support from Birlas of the Hazari report fame and all that; that is not going to solve the problem. Therefore, please take this as a warning for a bigger thing to come, this bigger thing of mass protest, which you should try to cure not by means of trying to impose military dictatorship in this country but by means of conceding the democratic demands of the people and by seeking faithfully to translate even your own pronouncements on the question of the rights of the workers, peasants, middle classes and so on.

This is my appeal. And this appeal should not be treated as minus any strength. We have got some strength and the Democratic Front has got far more strength than the Congress in Bengal. I will give a small example, though I do not want to go into the details. Take the middle classes, the educated people. In the Roorky Engineering college engineers are trained but they are unemployed. Machines are brought but factories are closing down. When the Prime Minister went to give them some convocation address or some such thing, they all walked out. Have all these middle class engineers turned Communists? No. It is sheer criticism of the system that is before them.

The masses are getting desperate and you are also getting desperate, because you cannot hold them back. So, in the class of these two desperations, if a dictatorship intervenes and tries to solve it, it is no solution either for your line or for our line, if at all your line is based upon your original thinking, which it is not. Therefore, my appeal to all Congressmen, to all Members of Parliament, to all people, even to the people in the Swatantra Party who in this House have said "We agree with the suppression of the Bengal Government" is this. They do not know, their fate will not be better than ours when it comes to a real test. Their fate will not be better than ours. Now they may have certain mines and certain banks. Then one group of bankers may fight another group of bankers and you will be the loser and they will be the gainers; you will not be the gainer. In this quarrel of bankers, they should have taken some advice, some hint from us. They should not have extended support to the suppression of the Bengal Ministry.

SHRI PILOO MODY : While the bankers are fighting, you should be in a bunker!

SHRI S. A. DANGE : I am agreeable to that proposition. But the point is this, that

in order to put me in a bunker Shri Chavan will have to take the help of this bunk which is sitting by my side. And in this battle between a bunk and a gentleman who wants to use dictatorship, who will win everybody knows. Therefore, do not be so complacent. Ultimately, you will be the goat that will be sacrificed, and a fat one at that.

So, I do want to close with a request and a solemn prayer that I hope this country will not go down under the dictatorship of a party which has betrayed its promises, to be followed by a dictatorship which will be worse, if it is military dictatorship, though I have got some faith in the good sense of the army also. They also, I think, believe in some norms of democracy, though no democracy is allowed to them, so far as personal life and their collective life is concerned. Still, I hope the events in the future will be decided by the masses in action and not by the bayonets in action. That is my only submission to this House.

SHRI HANUMANTHAIYA (Bangalore): Sir, for over an hour we had the benefit of a lecture on Communism. The whole speech was full of the excellences of Communism and how the day a proletarian dictatorship is established in this country everything will turn into gold.

SHRI S. A. DANGE: There was none in Haryana; no Communist dictatorship.

SHRI HANUMANTHAIYA: So far as the Congress Party is concerned, Shri Dange knows that we are not the people who close our minds to beneficial ideas, be they from one party or the other. The strength of the Congress Party is in the absorption of good ideas, whereas the weakness of the Opposition parties is that they stick to their own ideas irrespective of consequences or irrespective of their application to this country. So far as I am concerned I would like to subscribe to any theory which makes this country prosperous and happy.

The other day we had plenty of literature supplied to us about the 50th anniversary of Russia. I like Russia; therefore, I do not mean any disrespect to it. Only by way of illustration I want to bring to the notice of my hon. friends one thing.

SHRI S. A. DANGE: Only, you do not like that it has lived 50 years. That is all.

SHRI HANUMANTHAIYA: For the last 50 years they have worked for economic progress but still are my hon. friend, Shri Dange, and his colleagues in a position to say that it has reached the full level of prosperity and plenty? If you survey the world picture, it is the Scandinavian countries—Denmark, Norway and Sweden—which have got the highest standard of life

SHRI S. A. DANGE: And yours? What about you?

SHRI HANUMANTHAIYA: If you go further south in Europe, it is Switzerland that has got the highest standard of life. If you come to Asia, it is Japan. Whether it is China or whether it is Russia, they are still lagging behind. That is an admitted fact. More so in foodstuffs. All the time they hold conference on peace. Some of them here are their followers. I very much wish that on the day of the Revolution, in the Red Square, before the Kremlin, there was some evidence of the peaceful intention of this Communist country. I would have very much liked that.

AN HON MEMBER: Why did you not ask the Prime Minister that she should not go there?

SHRI HANUMANTHAIYA: I have gone there.

Instead of parading the kind of foodstuffs they grow, the clothes they produce, the radios they manufacture which makes for human happiness, they exhibit the latest weapons of destruction. I do not support America. It may be that they have manufactured or are using them. It may be that the Russians have manufactured and are not using them. But have these Communist nations, which stand for the underdog and to fight poverty, really fought and succeeded in that war against poverty? The very fact that they are exhibiting weapons of war and might shows that they are more conscious of something other than what is called fighting poverty and making people happy and prosperous.

Shri Dange was making a very beautiful exposition of class war. I would like to ask my Communist friends whether the party bureaucracy in the Communist society is not the brahmin caste that he was condemning all the time. They are the people who get everything that is best, who enjoy

[Shri Hanumanthaiya]

power the most, who have got political as well as administrative power in their hands. No brahmin class ever enjoyed so much power and privilege as does the Communist Party bureaucracy in a Communist country.

SHRI VASUDEVAN NAIR (Peermade): Are you a brahmin yourself? Why are you so much touched by a reference to the brahmins?

SHRI HANUMANTHAIYA: He wanted that we should not divide people and rule. If we had really succeeded, as he says, in the policy of divide and rule, we would not have lost in 9 States. In fact, the quarrel within the Congress is so great and widespread that none of our leaders has been able to tackle it successfully. It is because of that we have lost the elections in many States. It is not because of the failure of our policies. That is not the correct picture to give to the country.

Here, listening to Mr. Dange's speech, I was struck with pain to see that every reference he made was to create an incitement in the ranks of jawans against the Army officers. I learn it on authority that this strategy of putting the jawans against the officers has been taken as a matter of strategy by the Communist Party. The Government has to be alert. Because they have failed by democratic methods to capture majority opinion in the country, they now think that it is very easy to capture the imagination of the armed forces in order to stage a revolution in the country... (*Interruption*).

SHRI S. A. DANGE: On a personal explanation. I did not say anything against the commanders or the officers of the Army. I was talking about the infantry men.

SHRI HANUMANTHAIYA: The way he was talking about the Army, the jawans being ruled and all that, clearly shows that he was speaking in a way that people who read all this, the people who are not well-educated in the Army, may get angry against the officers and prepare themselves for a revolution.

Then, he spoke of Nagas and other hill tribes. What was he doing all the time? He wanted to incite the people of Nagaland and of other hill areas against the Congress Government. When he referred to the recent incidents in Ranchi, where he spoke with such approbation of students who staged demonstration against the Prime Minister, he was doing the same kind of incitement. I remember an incident. Once on a high road, a cyclist was knocked down by a car. There was a photographer. Now, the man who was knocked down wanted to go to the hospital for treatment as soon as possible. This photographer said, "Don't go; stand like that. I want to take your photograph." It is something like that the Communist Party is doing in India. For his professional purposes, the photographer wanted the cyclist to bear the pain and stand there so that he could take a photograph. Here is a party which wants to exploit every opportunity, right or wrong, in order to create a situation so that they may establish their political dictatorship.

Sir, he was talking about the United Front. I submit to you, honestly, that some of us here, in this House—I cannot speak for all—are happy that there are non-Congress Ministries in India, particularly because this political power corrupts and absolute power corrupts absolutely—I have seen the mightiest of persons getting absolutely corrupt . . .

SHRI VASUDEVAN NAIR: Therefore, you are out of power.

SHRI HANUMANTHAIYA: I am happy to be out. Even if Mr. Ranga wants to embrace me or Mr. Dange wants to embrace me, I will keep myself aloof. I may tell you, and we are also students of history, we know what the Communists did to Chiang-Ki-Sheik who wanted to come to some compromise with the Communists. The Communist strategy is to get hold of opportunities of compromise and then swallow the other party lock, stock and barrel.

These are the things which are self-evident in their own propaganda books. Therefore, even if they want, no democrat will ever subscribe to the theory of coalition with the people who have no faith in democracy. If it is a United Front, let it be. The question that has arisen in the light of what has been said by Mr. Dange all the time for one hour is more the question of Front. Those who believe in democratic principles or institutions have to put up a common front against those who believe in prole-

tarian dictatorship and suppression of individual liberty and citizens' rights. Here is a warning for every one of us, be it Swatantrites or Jan Sanghies or PSP, here is a warning he has given : unless we have a United Front irrespective of our small differences regarding the working of democratic institutions, this country is sure to lose democracy; the Constitution that was so painstakingly framed is sure to be subverted by those elements who have no faith in democracy. I ask him honestly has the Communist Party any faith in democratic institutions or the Constitution ? Merely because there is a phrase, we are not going to be misled. If the German State, which is a Communist State, is called the German Democratic Republic, it is not going to be a democracy; if the other part of Germany is called the Republican Germany, it does not cease to be a democracy. Therefore, many a time most of us are misled by misleading slogans and names coined for political purposes. But in India people are too shrewd and, therefore, they see the things for themselves. It is for that reason that repeatedly the people of India rejected the Communist Party. If the virtues of the Communist Party were so great, by this time, by democratic processes, they would have had the majority not only in some areas; but throughout India . . . (*Interruptions*). If by democratic processes the Communist Party is going to get a majority, let them get. I will be the first man to accept their rule. When I made my speech in the Constituent Assembly when the Fundamental Rights Chapter was accepted, I had made the same observation . . .

SHRI S. A. DANGE :I promise that we would not liquidate him.

SHRI HANUMANTHAIYA : My friend is very generous to me. He says that he will not liquidate me nor will the Congress Party liquidate me. Therefore, I am safe between the two.

AN HON. MEMBER : Is he in the Congress ?

SHRI HANUMANTHAIYA : He was making a great point about the right to recall. Could I respectfully ask my hon. friend in what Communist country is there this right to recall ? At least we have the right to criticise the Ministers, criticise the man who crosses the floor and even bring him to odium. Could any such thing be done to any member of the Communist Party or a member of the Presidium in China or Russia ?

These things are hurled at the Congress which has done much to bring democracy into existence, safeguarding the rights and liberties to the people to the extent that we tolerated all the antics and illegal things that the West Bengal Government did for over six months. Let my hon. friends consider this. Was it democratic for some people to do this ? I would not make allegations against the Party because I have no proof. And I am not one of those who will make reckless allegations. Was it right for a Member of Parliament, Mr Bimalkanti Ghosh, to be man-handled in the way it was done? Please ask for a moment what will happen if any one of the Opposition Members received that treatment ? Probably there would be a furore in this House. Probably the tempers would have risen so much that some of the furniture would have been burnt here. But, the Congress Party, having been trained in restraint, self-control, we digested not only the injury but the insult also.

SHRI S. A. DANGE : Why did you beat Mr. Madhu Limaye in the Elections ?

SHRI HANUMANTHAIYA : So far as Mr. Madhu Limaye is concerned, I do not know the facts, I have written a letter to him which must be in his file, he knows it, sympathising and supporting him in his rights. I am not advocating that the Congress Party people must beat anyone. The tragedy staged was that Mr. B. P. Jha, a labour leader, was murdered. By whom ? I would ask the Communist Parties there to clarify, to prove who was responsible for this.

SHRI S. A. DANGE : Not we.

SHRI HANUMANTHAIYA : The chaos in governmental organization went to that pitch that when two sections of clerks were quarrelling in the Writer's Building, that is, the Secretariat in Calcutta, the Chief Minister went there to pacify but he was also slapped. That is the kind of democracy that was practised by the Ministry of the United Front. In fact most of us in the Congress Party were aggrieved that Government of India was hesitant, apologetic and could not take a firm and deter-

[Shri Hanumanthaiya]

mined stand against those forces which were subverting democracy. We are for safeguarding the rights of the poor. We want to stand by the underdog. In fact that is the only qualification by which the Congress is surviving today. May be we have done it not so satisfactorily as you expect—I concede that. But that is our main purpose. And what is the purpose in making the poor and the illiterate get into a mood of dis-satisfaction so as to destroy buses, trams, fields, crops and everything useful ?

Sir, the other day I was in Calcutta. There is not only tragedy but some comedy in the situation the Communist Parties have worked up. A man was going with a basketful of fruits to his house. A mob caught hold of him and asked him 'Keep the fruit basket down.' He had to obey because there were hundreds of them. Then they asked him 'How many people are there in your house ? He said 'I, my wife and three children. We are five in all.' 'Then take five fruits and leave the rest. We will distribute them', shouted the mob. That is the kind of mob rule that was rampant in the streets of Calcutta.

SHRI NAMBIAR (Tiruchirappalli): At least five fruits were given. It was not robbery, no dacoity.

SHRI HANUMANTHAIYA : I would ask Mr. Nambiar one question. As soon as he goes out of the Parliament House, if I rob him of his tie, his coat and pen and give them to the sweepers here, I would like to know, how he would feel.

SHRI NAMBIAR : I will do it gladly.

SHRI HANUMANTHAIYA : Instead of saying that he is glad after I have asked him, if he was so sincere about it, he would have given them and come into the House.

Sir, we have reached a stage where all of us in this country who have worked for a quarter of a century and more for the establishment of democratic institutions in this country, have to wake up. Those of us who have faith in democratic institutions, have to wake up. I may tell you that the real danger siren has been sounded by Shri S. A. Dange and his other colleagues. They have been giving the warning. We do not take note of it; merely because they speak in sweet language. They say it by way of a joke, we treat it lightly, and think that they are not going to do some such thing. I say, all parties which have faith in democracy have to safeguard it with their blood, with their sweat and with determination. Most of us who fought British imperialism, I assure you, are not going to be frightened by Dange or Nambiars. Even today he has asked us to go before the people. I tell you in all humility, let him address any meeting, and I shall also go and address the meeting. If he wants to be labour me, I am prepared for it, and if I do not win the masses over to my side, if such an opportunity is given to me, I would rather . . .

SHRI K. ANIRUDHAN (Chirayaiuki): Let him go to Calcutta and address the meeting in the Parade Grounds today. I would call Comrade Dange also to go there and address; let Shri Hanumanthaiya also go to Calcutta and address the meeting and let us see what would happen.

SHRI D. C. SHARMA (Gurdaspur) : Shri Hanumanthaiya can address a meeting anywhere.

SHRI HANUMANTHAIYA : This is parliamentary warfare and let it be there. Each party invites its speakers for its public meeting, and if the Congress Party invites me, I am prepared to go.

SHRI S. M. BANERJEE (Kanpur) : The Congress is dead in Bengal.

SHRI HANUMANTHAIYA : It is not my personal affair; therefore, I cannot go there without an invitation to me. Not only will I go if I am invited . . .

AN HON. MEMBER : He will go with police guard.

SHRI K. ANIRUDHAN : Even if the Congress invites him, unless the military accompanies him, he will not go there.

SHRI HANUMANTHAIYA : My hon. friends are obsessed with the idea of the military, because they want this proletarian dictatorship to be supported by the military.

SHRI K. ANIRUDHAN : That is a big problem, and my hon. friend will not be able to understand it.

SHRI HANUMANTHAIYA : Take the picture of Bengal and Haryana. Democratic Ministries were . . .

MR SPEAKER : So, he is coming to the subject now.

SHRI HANUMANTHAIYA : Generally, I do not differ from you, but I protest against this remark of yours.

MR. SPEAKER : No, let him please listen to me. Let him wait for a minute.

SHRI HANUMANTHAIYA : No, I would not.

MR. SPEAKER : I am sorry he has misunderstood me. Let him hear me first.

SHRI HANUMANTHAIYA : I must be heard before you say anything.

MR. SPEAKER : I am sorry he has misunderstood me.

SHRI HANUMANTHAIYA : I must be heard before you reply. I am not going to take it like that.

MR. SPEAKER : All right; let him go ahead.

SHRI HANUMANTHAIYA : When the Opposition Members speak . . .

MR. SPEAKER : Let him wait for a minute.

SHRI HANUMANTHAIYA: No, I would not wait.

When the Opposition Members wander all over the world and speak you listen to them patiently.

MR. SPEAKER : I shall give him some more time.

SHRI HANUMANTHAIYA : But when a Congress Member speaks, you are interfering, and you cut jokes and so on. I protest against this procedure.

MR. SPEAKER : I have said that I would give him time. I have not said that I would not give him more time.

Would the hon. Member kindly hear me ? I said that now he had begun his speech proper. All the while, he was replying to Shri S. A. Dange. I think he did not hear me properly; he did not understand me aright. All the while, all this half an hour or so, he was replying to Shri S. A. Dange, but now he has come to the subject of Bengal and Haryana. I have not even rung the bell. I thought that he would continue even tomorrow. I do not know why he got excited.

I thought that he was replying to Shri S. A. Dange all the while and now he had come to the subject. It is not that he has to finish in three minutes. I do not want Shri Hanumanthaiya to finish even in these three minutes that remain today; he can continue his speech tomorrow, because Shri S. A. Dange also had taken one hour nearly, and he has taken only about 25 minutes; I do not mind his taking another 10 or 15 minutes more tomorrow also. I think he did not hear me properly, nor did he understand me properly.

I was thinking that till now he was replying to Shri S. A. Dange's speech. That was exactly what I meant.

SHRI S. A. DANGE : I am afraid you are doing some injustice to me . . .

MR. SPEAKER : Let both the hon. Members resume their seats.

SHRI S. A. DANGE : I think you are doing some injustice to me when you say that, because he was not replying to me; he was only discussing the Soviet Union and all that, about which I never spoke at all.

MR. SPEAKER : I do not know why there should be any excitement. Let there be no excitement here. I never meant anything against anyone. I was only saying that Shri Hanumanthaiya was coming just now to the subject of the no-confidence-motion; namely Bengal and all those things; this is for the first time that he has mentioned those names. I thought that till now he was replying to some theoretical things about democracy about communism and all that. That was good. I did not want him to finish in the next three minutes. I had not rung the bell even once so far. I want him to speak for another fifteen minutes or so tomorrow morning also. I have absolutely no objection to that. I have not rung the bell even once today for him. I do not know how he thinks that I am not allowing him.

Let him continue now. I have never rung the bell also till now.

SHRI HANUMANTHAIYA : I am guided by your advice. Let this incident pass.

SHRI D. C. SHARMA : It has passed.

SHRI S. M. BANERJEE : He is a misguided missile.

SHRI HANUMANTHAIYA : Shri Dange made a great virtue . . .

SHRI D. C. SHARMA : He has come back to Shri Dange again.

SHRI HANUMANTHAIYA : . . . . out of the gherao that some people staged against the High Court.

SHRI S. A. DANGE : We are talking about Haryana. He forgets that.

SHRI HANUMANTHAIYA : Tomorrow I will continue. I will deal with Bengal and Haryana first as he suggests.

MR. SPEAKER : May I now ring the bell and say that it is 6 O'clock now and he might continue tomorrow ?

The House stands adjourned till 11 A.M. tomorrow.

18.00 HRS.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Thursday, November 23, 1967/Agrahayana 2, 1889 (Saka).